WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

वर्षः 01 अंक : 246 | लखनऊ, बुधवार, 26 अगस्त, 2020 | पृष्ठ- 6 | मूल्य - 1 रुपये

कंगना रनौत ने बाय काट कंगना पर दिया मुंहतोड़ जवाब

एक दिन में रिकार्ड 66,550 कोरोनामुक्त

सक्रिय मामले हुए कम

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना महामारी की बढ़ती विकरालता के बीच पहली बार एक दिन में 66 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं और इसकी तुलना में संक्रमण के नये मामलों की संख्या कम रहने से सक्रिय मामलों में छह हजार से अधिक की कमी आयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 66,550 लोगों को संक्रमण से छुटकारा मिला है जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 24,04,585 हो गयी है। इस दौरान संक्रमण के 60,975 नये मामले सामने आने से सक्रिय मामलों में 6,423 की कमी आयी है। देश में संक्रमितों की संख्या 31,67,324 हो गयी

है तथा सक्रिय मामले 7,04,348 हो गये हैं। देशभर में पिछले 24 घंटों के दौरान 848 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 58,390 हो गयी। देश में सक्रिय मामले 22.24 प्रतिशत और रोगमुक्त होने वालों की दर 75.92 प्रतिशत है जबकि मृतकों की दर 1.84 प्रतिशत है। कोरोना से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या सबसे अधिक 3416 घटकर 1,68,443 रह गयी तथा 212 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 22,465 हो गया। इस दौरान 14,219 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 502490 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान मरीजों की संख्या 226 कम होने से सक्रिय मामले 89,516 हो गये। राज्य में अब तक 3368 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8,741 लोगों के स्वस्थ होने से कुल 2,68,828 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं। कोरोना संक्रमण मामलों में पूरे देश में चौथे स्थान पर स्थित दक्षिणी राज्य कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या में 2,337 की कमी हुई है और यहां अब 81,230 सक्रिय मामले हैं।

सिब्बल के नये ट्वीट से कांग्रेस में 'घमासान' बाकी होने के संकेत

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में श्रीमती सोनिया गांधी को फिर से अंतरिम अध्यक्ष चुन लेने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि वरिष्ठ नेताओं के बीच तल्खी खत्म हो गई किंतु पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के मंगलवार को किए ट्वीट से आभास होता है कि घमासान अभी बाकी है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सोमवार को बैठक में बयान के बाद ट्वीट करने वाले देश के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक श्री सिब्बल के आज के ट्वीट से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यह किसी पद की बात नहीं है।

यह मेरे देश की बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। श्री सिब्बल ने सोमवार को बैठक में श्री गांधी की नाराजगी वाली रिपोर्ट के बाद भी ट्वीट किया था, किंतु बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता ने ट्वीट यह कहते हुए हटा लिया था कि श्री राहुल ने उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को बैठक से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद समेत पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती गांधी को संगठन में बदलाव के लिए एक पत्र लिखा था। इस पत्र के बाद से पार्टी में भूचाल मचा हुआ है।

पुलवामा जैसा दूसरा अटैक करने वाले थे आतंकी

बालाकोट एयरस्ट्राइक से डरे मसूद अजहर ने रोका

जम्मू, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकवादी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के मामले में मंगलवार को जम्मू में विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया। इसमें आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 19 लोगों के नाम हैं। जांच एजेंसी द्वारा दायर 13,500 पन्नों के इस आरोप पत्र में आत्मघाती हमले की हर गुत्थी सुलझाई गई है। पिछले साल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर हुए उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आतंकवादी यहीं नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने ऐसे ही एक और हमले को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली थी। कार की व्यवस्था कर ली गई थी। फिदायीन तैयार भी तैयार थे, लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद

के ट्रेनिंग सेंटर पर बम बरसा दिए। भारत की आक्रामकता और पाकिस्तान पर पड़े अंतरराष्ट्रीय दबाव में दूसरे हमले को रोका गया। चार्जशीट में दिए गए सबूतों के बारे में बताते हुए एक सूत्र ने बताया कि मसूद अजहर ने तुरंत उमर फारूख को मैसेज किया और दूसरे हमले को रोकने को कहा। उमर फारूख मसूद अजहर का भतीजा और आईसी-814 हाइजैकिंग में शामिल रहे इब्राहिम अतहर का बेटा है, जो पुलवामा हमले के डेढ़ महीने बाद ही एनकाउंटर में मारा गया था। आरोप पत्र में अजहर के अलावा अलग-अलग मुठभेड़ में मारे गए सात आतंकवादियों, चार भगोड़ों का नाम शामिल है। इनमें से दो भगोड़े अब भी जम्मू-कश्मीर में छिपे हुए हैं, जिनमें एक स्थानीय निवासी और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है।

14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चल सकता है संसद का मॉनसून सत्र

कोरोना के चलते होंगे कई बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश की है कि 14 सितंबर से एक अक्टूबर तक मॉनसून सत्र चलाया जाए। कोरोना वायरस की वजह से देर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में इस बार कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। उचित दूरी का पालन करते हुए सदस्यों के बैठने के लिए दोनों चैंबरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल होगा। राज्यसभा सचिवालय

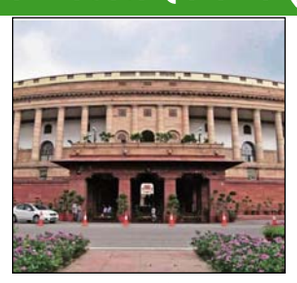

के मुताबिक, सत्र के दौरान ऊपरी सदन के सदस्यों को दोनों चैंबर और दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी जहां 60 सदस्य चैंबर में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्य लोकसभा के चैंबर में बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। वहीं, राज्यसभा चैंबर के भीतर प्रधानमंत्री, सदन के नेता, विपक्ष के नेता और अन्य दलों के नेताओं के लिए सीटें चिन्हित की जाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री-मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौड़ा के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सदस्य- रामविलास पासवान और रामदास आठवले के लिए भी सदन के चैंबर में चिन्हित सीटें होंगी। अन्य मंत्रियों को सत्तारूढ़ सदस्यों के लिए तय सीटों पर बैठाया जाएगा।

प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में नहीं हो रहा कोई सुधार

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में मंगलवार को कोई सुधार नहीं हुआ और वह वेंटिलेटर पर हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी। चौरासी वर्षीय मुखर्जी का उपचार कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें श्वांस संबंधी संक्रमण है, जिसका इलाज चल रहा है। वह अभी वेंटिलेटर पर हैं। मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली छावनी स्थित इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा, प्रणब मुखर्जी की हालत में कल से कोई बदलाव नहीं आया है। वह गहरे कोमा में हैं। वह अभी वेंटिलेटर पर हैं। उनके स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण मानक स्थिर हैं। मुखर्जी के मस्तिष्क में खून के थक्के जमने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया था। अस्पताल में भर्ती कराए जाने के समय वह कोविड-19 से भी संक्रमित पाए गए थे।

सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कुछ नेता बोले

हम विरोधी नहीं, पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कुछ ने मंगलवार को कहा कि उन्हें विरोधी नहीं समझा जाए और उनको पार्टी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस कार्य समिति की हंगामेदार और मैराथन बैठक के एक दिन बाद इन नेताओं ने यह भी कहा कि पत्र लिखने का मकसद कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अविश्वास जताना नहीं था और अब सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी, उन्हें मंजूर होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने ट्वीट किया कि यह पद के लिए नहीं है। यह मेरे देश के लिए है, जो सबसे

ज्यादा महत्व रखता है।

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने यह टिप्पणी उस वक्त की है कि जब एक दिन पहले ही बॅब् बैठक में राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी और फिर उन पर सिब्बल की तरफ से निशाना साधे जाने के बाद विवाद हो गया था। बाद में सिब्बल ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें सूचित किया कि उनके हवाले से जो कहा गया है वो सही नहीं हैं और ऐसे में वह अपना पहले का ट्वीट वापस लेते हैं। पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने ट्वीट किया कि हम विरोधी नहीं हैं, बल्कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के पैरोकार हैं। यह पत्र नेतृत्व को चुनौती देना नहीं था, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कदम उठाने के लिए था। चाहे अदालत हो या फिर सार्वजनिक मामले हों, उनमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ कवच होता है। इतिहास बुजदिल को नहीं, बहादुर को स्वीकारता है। इनके इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा कि इस पत्र को अपराध के तौर पर देखने वालों को आज नहीं तो कल, इसका अहसास जरूर होगा कि पत्र में उठाए गए मुद्दे विचार योग्य हैं। वासनिक ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरी तरफ, इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक अन्य नेता ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा कि सीडब्लूसी बैठक में जो नतीजा निकला, उससे हम संतुष्ट हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई नेता सीडब्लूसी की बैठक में मौजूद थे और सबने प्रस्ताव पर सहमति जताई।

प्रशांत भूषण मामला उपयुक्त पीठ को सौंपने का निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। अदालत की अवमानना मामले में दोषी पाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सिर्फसजा देने का नहीं है, बल्कि संस्था में भरोसे का भी है, जिसके लिए विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसी के मद्देनजर मामले को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाएगा। यह अवमानना मामला साल 2009 में तहलका पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार के दौरान न्यायपालिका पर भूषण की टिप्पणियों से जुड़ा है।न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन से कहा कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि लोग राहत पाने के लिए अदालत आते हैं और अगर यही विश्वास हिल जाए तो यह एक समस्या की बात है।

अवमानना केसः अटॉर्नी जनरल ने एससी से कहा

प्रशांत भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दें

नई दिल्ली, एजेंसी। अवमानना के लिए दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण के मामले में मंगलवार को एक बार फिर सुनवाई हुई, जिस पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनको माफी दे देनी चाहिए और चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उनका कहना है कि वह अवमानना के लिए माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल अपने आदेश के जरिए ही अपनी बात रख सकती है। अपने हलफनामे में भी प्रशांत भूषण ने अपमानजनक टिप्पणी की है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ध्वस्त हो गया है, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है, शीर्ष अदालत की पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। कोर्ट ने कहा कि प्रशांत ने शीर्ष अदालत की गरिमा और गंभीरता को नहीं समझा जिससे कोर्ट की छवि

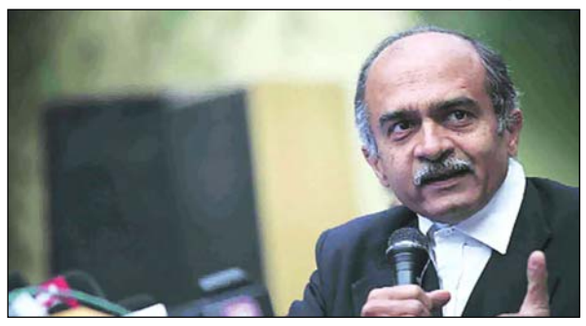

को गहरा आघात लगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत अपनी गलती पहले ही मान जाते और माफी मांग लेते तो मामला यहां तक नहीं पहुंचना था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्त्ता-अधिवक्ता प्रशांत भूषण तथा पत्रकार तरुण तेजपाल के खिलाफ2009 के अवमानना मामले को मंगलवार को दूसरी पीठ को सौंपने का फैसला किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि यह मामला काफी समय से लंबित है, इसे 10 सितंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। दो सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए समय चाहिए अतरू इसे एक उपयुक्त पीठ को सौंपते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।

भरभराकर गिरा तीन मंजिला मकान, मलबे में कई लोग दबे

देवास, एजेंसी। देवास में स्टेशन रोड पर नई आबादी में एक तीन मंजिल मकान भरभरा कर ढह गया। इस मकान के मलबे में कुछ लोगों व बच्चों के दबने की संभावना है। पुलिस व प्रशासन मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि मकान जाकिर शेख आरामशीन वालो का है। इस मकान में चार भाईयों का अलग अलग परिवार रहता है। घटना के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस व बचाव दल ने राहत कार्य शुरु कर दिया है। मलबे के नीचे और भी लोग दबने की आशंका जताई जा रही है। नगर निगम और पुलिस मौके पर मौजूद है।

एनपीआर बहाना, मोदी सरकार का चुनाव पर निशाना

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी चुनाव के लिए क्या कुछ कर जाती है, इस बात से हर कोई वाकिफहै,अब बिहार और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है,यहां तक कि केंद्र के उन फैसलों में बदलाव किया जा रहा है. जिसका ढोल तमाम नेता बजाते आ रहे थे,जी हां एनपीआर को लेकर सरकार झुकने को राजी हो गई है उसने गुपचुप तरीके से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को लेकर पूरा देश आवाज उठाता रहा3विपक्ष ने सरकार के कदम की आलोचना की,यहां तक कि नीतीश ने भी अलग राग अलाप लिया,लेकिन मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे..लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव और पश्चिम बंगाल चुनाव की आहट हुई,वैसे ही मोदी सरकार मुलायम हो गई..और गुपचुप तरीके से कदम पीछे खींच लिए, जीहां एनपीआर में पूछे जाने वाले विवादित सवाल सरकार ने हटा लिए हैं3 अब एनपीआर के तहत पूछे जाने वाले सवालों में से मातृभाषा, माता-पिता के जन्म की तारीख और स्थान वाले सवाल आधिकारिक वेबसाइट से हटा लिए गए हैं. अब केवल व्यक्ति का नाम, घर के मुखिया से रिश्ता, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, लिंग, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान पूछा जाएगा,इस सूची से मातृभाषा के बारे में सवालों को छोड़ दिया गया है,यहां तक कि आधार नंबर का खुलासा करना भी वैकल्पिक है,मोदी सरकार के इस कदम से साफहै कि वो चुनाव के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ...गौरतलब है कि झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत 11 राज्यों ने एनपीआर के खिलाफप्रस्ताव पारित किए थे3यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि एनपीआर को उनके राज्य में उस रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें विवादास्पद प्रश्न शामिल हैं और केवल 2011 के प्रारूप के अनुसार आयोजित किए जाने की अनुमति हो सकती है,इस रुख के बाद भी सरकार नहीं झुकी लेकिन जैसे ही चुनावी दस्तक हुई, वैसे ही सरकार ने पलटी मार ली,इसके बाद कहा जा सकता है कि मोदी सरकार चुनाव के लिए कुछ भी करेगी।

राहुल गांधी का वार

महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम,जनता को लूटे सरकार खुलेआम

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस संकटकाल के बीच पेट्रोल के दाम लगातार छठे दिन बढ़े हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब इस मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंगलवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 11 पैसे महंगा हो कर 81.73 रुपए पर पहुंच गया है। अगर पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो हर रोज पेट्रोल के दाम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की गई है। वहीं, पिछले दस दिनों में नौ बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। दिल्ली में पिछले दस दिनों में पेट्रोल करीब 1.30 रुपए महंगा हो गया। हालांकि, लंबे वक्त से डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 81.73 रुपए, 83.24 रुपए, 88.39 रुपए और 84.73 रुपए प्रति लीटर हो गई है।

कोरोनाकाल में बीजेपी के आयोजनों से कोर्ट नाराज

ग्वालियर, एजेंसी। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में भीड़ जमा करने पर पाबंदी है। बावजूद इसके बीजेपी ने ग्वालियर के फूलगांव में सदस्यता ग्रहण समारोह का उच्च स्तरीय आयोजन किया गया। जिस पर अब ग्वालियर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए राज्य के अफसरों से नाराजगी जताई है कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति क्यों और किस आधार पर दी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर भिंड कलेक्टर और एसपी सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और प्रदेश सरकार के दिशानिर्देशों का हर हाल में पालन करवाएं। अफसर देखें कि कोविड-19 को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों का किसी भी बड़े आयोजन में कोरोना काल के निर्देश का पालन किया जा रहा है या नहीं।

देश में चल रहा है तीन वैक्सीन का परीक्षण टीके को लेकर रूस के संपर्क में है सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस पर मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस में आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर (डॉ.) बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में तीन कोविड-19 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन का 2 (बी) फेज और 3 फेज टेस्ट चल रहा है। भारत बायोटेक और जेडस कैडिला की वैक्सीन ने 1 फेज का टेस्ट पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 10 टेस्ट प्रतिदिन, 15 मार्च 1000 टेस्ट प्रतिदिन, 15 मई 95000 टेस्ट और 21 अगस्त को हम 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन के लैंडमार्क पर पहुंच गए हैं। ज्ञात हो कि भारत में मंगलवार से पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआई आई), ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना

वैक्सीन का फेज-2 क्लीनिकल ट्रायल शुरू करने जा रहा है। पुणे के भारती विद्यापीठ चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए स्वस्थ वयस्कों पर अध्ययन किया जाएगा। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बनाने के लिए ब्रिटिश-स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ साझेदारी की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने 3 अगस्त को सीरम को देश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ह्यूमन ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। ट्रायल 17 चयनित जगहों पर आयोजित किए जाने हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि आज देश में ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केसों से 3.4 गुनी ज्यादा है। रिकवर हुए मरीजों की संख्या 24 लाख से अधिक है। कुल मामलों के 22.2 प्रतिशत केस एक्टिव हैं। रिकवरी रेट 75 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। अब तक 3 करोड़ 60 लाख टेस्ट हो चुके हैं। राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों में 6423 की गिरावट दर्ज हुई है। कुल एक्टिव मामलों में से कुल 2.70 प्रतिशत मामले ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। एक्टिव मामलों में से 1.92 प्रतिशत मरीज ही आईसीयू में है और 0.29 प्रतिशत वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.58 फीसद है जो दुनिया में सबसे कम है।

उत्तर प्रदेश में जंगलराज, पत्रकारों की हत्या से दहला प्रदेश:अजय कुमार लल्लू

➲ पत्रकारों को निगल रहा है योगी का जंगलराज ➲ प्रदेश की कानून व्यवस्था हुयी लकवाग्रस्त, प्रदेश में जंगलराज कायम ➲ महिलाएं, पत्रकार, आम आदमी बढ़ते अपराध से सहमे ➲ कोरोना की गति को पछाड़ कर अपराध ने टॉप किया प्रदेश में ➲ एक महीने में 124 हत्याएं, और पिछले तीन महीने में तीन पत्रकारों की हत्या योगी के रामराज्य की कलई खोलता है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बलिया के पत्रकार रतन सिंह के परिजनों से मिलने जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रायबरेली के सलोन के पास पुलिस हिरासत में लिए जाने की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि योगीराज में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है ।प्रदेश अपराध का हब बन चूका है और अपराधी इतने मनबढ़ हो चुके है कि अब पत्रकारों की सरेआम हत्या आम हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जारी बयान में कहा कि बलिया के पत्रकार रतन सिंह की सरेआम हत्या ने योगी राज की कलई खोल कर रख दी है। रामराज्य का दावा करने वाले योगी जी के हाथ से प्रदेश की कानून व्यवस्था निकल चुकी है. चौतरफा अराजकता का साम्राज्य है। अपराधियों की सबसे सुरक्षित धरती उत्तर प्रदेश हो गयी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि प्रदेश में जंगलराज कायम हो चुका है और कानून के राज को लकवा मार चुका है। आज उत्तर प्रदेश बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहा है और आम आदमी के जानमाल की सुरक्षा की एकदम गारंटी नहीं है। अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि प्रदेश की महिलाएं, पत्रकार और आम आदमी इस बढ़े हुए अपराध से सहमें हुए हैं लेकिन योगी सरकार आम आदमी को सुरक्षा का एहसास कराने में बुरी तरह से नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कोरोना को मात दे चुका है। अजय कुमार लल्लू ने आगे कहा कि यह कैसा प्रदेश योगी जी बना रहे हैं जहां एक महीने में ही 124 हत्याएं होती हैं और तीन माह में तीन पत्रकार मार दिए जाते हैं। यही नहीं सरकार अपनी असफलता छिपाने के लिए 11 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराती है। इस जंगल राज के खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। योगी आदित्यनाथ को आवाम को जवाब देना पड़ेगा। पुलिस हिरासत में लिए गए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महासचिव मनोज यादव, किसान कांग्रेस अध्यक्ष तरुण पटेल, लखनऊ जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, शहर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान आदि शामिल थे।

हमीरपुर जा रही बाइक सवार महिला की मार्ग दुर्घटना में मौत

अमौली, फ्तेहपुर । चांदपुर थाने के अंतर्गत गांव मेहंदीयापुर निवासी कौशल्या देवी पत्नी हेमराज अपने किसी निजी न्यायालय के काम से हमीरपुर जा रही थी। रास्ते में मध्यान्ह 12.30 बजे सामने से आ रहे मोरंग के डंपर जिसका नंबर न्च्33ठज्0173 ने बाइक सवार महिला की बाइक में जोरदार टक्कर मारी जिसमें बाइक चालक मदन सिंह गाड़ी से टक्कर खाकर दूर गिरा और बाइक में बैठी महिला कौशल्या के चीथड़े उड़ गए। महिला की मौके पर ही मौत हो जाने पर आनन फानन पुलिस प्रशासन थाना सजेती मौके पर पहुंचा तब तक गाड़ी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। गाड़ी को कब्जे में लेकर कानपुर जनपद के थाना सजेती पहुंचाया गया तथा मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक महिला की तीन बेटियां एवं दो बेटे हैं जिसमें अभी तक केवल एक बेटी का ही कन्या दान मृतका कौशल्या देवी कर पाई थी। पोस्टमार्टम के पश्चात आज मृतका का शव उसके गांव सठिगवां के पास थाना चांदपुर के अंतर्गत मेहंदीयापुर लाया गया। पुलिस प्रशासन की जानकारी के अनुसार गाड़ी रायबरेली जनपद की बतायी जा रही है।

उमेश पाल बने राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक

फ्तेहपुर । राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले 'मंडल मसीहा पूर्व मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल' की जयंती 'डा. अमित पाल (प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा)' की अध्यक्षता में मनाई गई। डा. पाल ने अपनी बात रखते हुए लोगों को जानकारी दी कि भारत के संविधान में सभी वर्गों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई है. जिसके आधार पर संविधान लागू होते ही एससी और एसटी को उनकी संख्या के आधार पर 22.5: रिजर्वेशन लागू हुआ पर ओबीसी को उसकी संख्या के आधार पर आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। इतना ही नहीं ओबीसी की आज तक ओबीसी के नाम पर गिनती भी नहीं की गई। चाहे देश में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की दोनों ने ही ओबीसी के हक और अधिकारों को लागू होने नहीं दिया। वो तो जनतादल के समय में काशीराम साहब, देवी प्रसाद, लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव आदि नेताओं के दबाव वश बी.पी. मंडल द्वारा 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत की तैयार की गई। रिपोर्ट को लागू करवाने की मांग की गई जिसे लागू करने में भी धोखेबाजी की गई और न्यायालय द्वारा 52 प्रतिशत ओबीसी को मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया जिसमें ऊपर से क्रीमीलेयर का भी षड्यंत्र किया गया जिसकी जानकारी हमारे ओबीसी के लोगों को आज तक नहीं है। बैठक में उमेश पाल (प्रधान मल्हीपुर) को राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला संयोजक की जिम्मेदारी दी गई. जिसें प्रधान ने सहर्ष स्वीकार किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बाबूलाल पाल, दिनेश पाल, धरम पाल, रघुवीर पाल, जिया लाल फौजी आदि लोग उपस्थिति रहे।

चतुरी का पुरवा में अधूरे पड़े मार्ग को अतिशीघ्र बनवाने की मांग

फ्तेहपुर । उद्योग व्यापार मण्डल का एक प्रतिनिधि मण्डल जिलाधिकारी से मिला और शहर के मध्य पटेल नगर स्थित चतुरी मुराई के पुरवे में हेमराज के घर से जगदीश भारतीय के घर तक अधूरे पड़े लगभग 50 मीटर सीसी रोड इंटरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल ने कहा कि चतुरी मुराई का पुरवा आईटीआई रोड के पीछे, पटेलनगर में नगर पालिका परिषद द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व रोड का अधूरा निर्माण कराया गया, जिसकी वजह से वंचित व छूट गई रोड काफी नीचे हो जाने के कारण जलभराव की समस्या सदैव बनी रहती है। जलभराव वाले स्थान पर विद्युत पोल आवंटित होने की वजह से विद्युत करेन्ट का खतरा सदैव बना रहता है। कभी भी जनक्षति की आशंका से इंकार नही किया जा सकता है। उपरोक्त समस्या के निदान हेतु पिछले एक वर्ष से समक्ष अधिकारियों को प्रार्थना पत्र के माध्यम से निदान हेतु प्रयास किया जा चुका है, परन्तु समस्या ज्यो की त्यों बनी हुई है। जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों व राहगीरों को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जलभराव व विद्युत पोलो में करेन्ट की विकराल समस्या के निदान हेतु वंचित रोड का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस मौके पर व्यापार मण्डल अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा, स्थानीय निवासी, अतुल भारतीय, शिवम भारतीय, सोनू, रवि, शंकर ,जगदीश, जगदेव, रमेश आदि मौजूद रहे।

विद्युत बिल जमा होने के बावजूद काटा कनेक्शन

➲ कनेक्शन जोड़े जाने के बाद धरना किया गया समाप्त
➲ भाकियू ने पावर हाउस में दिया धरना

बिन्दकी, फ्तेहपुर । विद्युत बिल जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन काट देने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने पावर हाउस परिसर में धरना दे दिया और मांग किया कि जब तक कनेक्शन जोड़ा नहीं जाएगा धरना जारी रहेगा भारतीय किसान यूनियन की मांग को लेकर कनेक्शन जोड़ा गया जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने धरना समाप्त कर दिया।

मंगलवार को अचानक भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने नगर के नजा ही बाजार पावर हाउस परिसर में धरना शुरू कर दिया भारतीय किसान यूनियन के लोगों का आरोप था कि नगर के मोहल्ला जहान पुर निवासी राम दुलारी देवी पत्नी किशन कुमार का बिजली का बिल पूरा जमा था इसके बावजूद भी कनेक्शन काट दिया गया धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने मांग किया कि जब तक रामदुलारी का कनेक्शन जोड़ा नहीं जाता धरना जारी रहेगा इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे रामदुलारी का कनेक्शन तत्काल प्रभाव से जोड़ा गया इसके बाद भारतीय किसान यूनियन के लोगों का धरना समाप्त हुआ इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष रामसहाय पटेल मलवा ब्लाक अध्यक्ष नवल सिंह पटेल के अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता पुन्नू शुक्ला के अलावा कसान सिंह मोइन अहमद दिलीप तिवारी जगदीश कुमार राजकुमारी देवी किशन कुमार मुशीर हुसैन सहित तमाम भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सृजन अभियानः कांग्रेसियों ने भाजपा सरकारों को कोसा

बिन्दकी, फ्तेहपुर । नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित खजुहा बागबादशाही में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने संगठन सृजन अभियान के तहत बैठक की। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने सत्ता में आसीन लोगों को जमकर लताड़ लगाई। युवा कांग्रेसी नेता बबलू कालिया ने देश के किसानों की लगातार हो रही आत्महत्या को लेकर सीधे देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा तो वहीं एक और पदाधिकारी ने देश व प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारी पर प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किये। बैठक में संविधान व संवैधानिक संस्थाओं तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अखिलेश पाण्डेय ने लोगों से कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर वर्तमान सरकार के कुशासन के खिलाफसंघर्ष करने की अपील की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष अखिलेश तिवारी, उपाध्यक्ष राजीव लोचन निषाद, महासचिव बबलू कालिया, महासचिव उदित अवस्थी, पंकज गौतम, जिला सचिव अरुण कुमार तिवारी, सभासद शोएफ रहमान कुरैशी, इमरान अली, इमरान सिद्दीकी, यासीन कुरैशी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सीओ जाफरगंज ने गाजीपुर थाने का किया निरीक्षण

➲ मिलीं खामियों को अतिशीघ्र दुरूस्त करने का सुनाया फरमान

फ्तेहपुर । पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जाफरगंज द्वारा थाना गाजीपुर के निरीक्षण के क्रम में थाना कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों, रजिस्टरों का अवलोकन किया गया, अभिलेख अवलोकनोपरान्त शस्त्रागार, कम्प्यूटर कक्ष, बैरक, भोजनालय, हवालात, बाथरूम आदि का निरीक्षण किया गया। अभिलेखो व शस्त्रागार का रख रखाव संतोजनक पाया गया। थाने पर उपस्थित कर्मचारीगण से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्विक स्तर पर फैली महामारी कोविड-19 के मद्देनजर साफ-सफाई एवं सुरक्षा के विषय में सावधानी बरतने हेतु बैरकों, भोजनालय व कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उचित दूरी रखी जाय तथा कम्प्यूटर कक्ष की चेकिंग के दौरान कम्प्यूटर उपकरणों के रखरखाव हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसी प्रकार थाने पर बने कोविड केयर हेल्प डेस्क पर प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित से स्वयं की थर्मल स्क्रिनिंग, पल्स ऑक्जीमीटर एवं अन्य उपकरणों की सहायता से की जाने वाली जांचों की स्थिति का अवलोकन किया गया तथा महिला हेल्प डेस्क के कार्यों व अभिलेखो का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिया गया। थाना परिसर भम्रण के दौरान साफ-सफाई एवं मालो के रखरखाव, निस्तारण हेतु तथा थाना क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त, फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये गये। भूमि विवादों मे समयबद्ध कार्यवाही, शराब माफिया, टापटेन अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही तथा शिकायती प्रार्थना पत्रो के समयबद्ध निस्तारण, पंजीकृत अभियोगो की विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण, मुकदमों मे प्रभावी पैरवी, एन0सी0आर0 के प्रकरणों मे प्रभावी कार्यवाही करते हुए सर्तक दृष्टि रखने व जेल से छूटे हुए अपराधियों का सत्यापन/निगरानी एवं हिस्ट्रीशीटरों/पुराने अपराधियों के गतिविधियों पर सर्तक दृष्टि रखते हुए निगरानी व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें की प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों का समयबद्ध न्यायालय में परीक्षण कराकर दोषियों को सजा दिलाने के सार्थक प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा शासन द्वारा चलायें जा रहे।

जिले से विलुप्त होती जा रही ज्वार की फसल

फ्तेहपुर । खागा तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ज्वार की खेती होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षो से किसान साल दर साल ज्वार की खेती से दूर होते जा रहे हैं। फसल तैयार होने में अधिक समय लगने की वजह से अब बहुत कम किसान इसकी खेती करते हैं। विजयीपुर के किसान रघुवीर प्रसाद त्रिपाठी की माने तो ज्वार की फसल पकने में एक लम्बा वक्त लगने के चलते रखवाली में आने वाली परेशानियों के कारण अब किसान ज्वार की खेती नहीं करते। किसान धर्मवीर त्रिपाठी व देवीसहांय तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में नीलगाय बहुतायत मात्रा में हैं जो ज्वार की फसलों को एकदम चट कर डालती थी जिससे इस खेती से मन विचलित हो गया है। उनका यह भी कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को इस फसल का लाभ दिलाने में नाकाम है।

बताते चलें कि लगभग डेढ़ दशक पूर्व तक कस्बाई इलाकों में ज्वार की खेती खूब होती थी। खास तौर पर विजयीपुर व यमुना छोर पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। साथ ही अन्य ब्लाकों में किसान खरीफ के सीजन में फसल बोते थे। इसका आटा बेहद पौष्टिक माना जाता है। वहीं ज्वार का तना व पत्ते अच्छा पशुआहार भी हैं। इन सबके बावजूद साल दर साल किसान ज्वार से दूर होते जा रहे हैं। ज्वार की फसल ढलानदार खेतों में बोयी जाती है या फिर जिन खेतों में अच्छी जल निकासी हो वहां इसकी पैदावार खूब होती है। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ज्वार के लिए बलुई दोमट व भारी मिट्टी बेहद उपयोगी होती है। आमतौर पर खरीफ सीजन से जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक ज्वार की बुआई की जाती है। एक हेक्टेयर खेत में 10 से 12 किलो ज्वार बोई जाती है। इसके बाद फसल की रखवाली करना बेहद आवश्यक हो जाता है। ज्वार के भुट्टा निकलते वक्त तथा दाना भरते समय यदि खेत में नमी कम हो तो पानी की आवश्यकता रहती है। यदि पानी न बरसे तो किसानों को फसल में सिचाई करनी चाहिए, चूंकि खरीफ सीजन की मुख्य फसल उर्द व मूंग को पकने में 100 से 110 दिनों का समय लगता है। ऐसे में किसान उर्द, मूंग अधिक बोते हैं। उर्द, मूंग की कटाई होने के बाद ज्वार की फसल की रखवाली करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहता। होता यह है कि यदि एक किसान ने ज्वार की फसल बोयी है तो आसपास के किसान उर्द, मूंग की फसल बोते हैं और समय से फसल काट लेते हैं। ऐसे में जिस किसान ने ज्वार बोयी है, उसे कई दिनों तक अकेले ही अन्ना मवेशियों व नीलगायों से फसल की निगरानी करनी होती है। ऐसे में यह बेहद मुश्किल काम होता है, इसलिए किसान ज्वार की खेती से दूर होते जा रहे हैं जो बेहद चिंता का विषय है।

विलुप्त होती जा रही ज्वार के आटे के कई व्यंजन प्रसिद्ध हैं। खासतौर पर किसानों को चने व पालक की भाजी के साथ ज्वार की रोटियां खूब भाती हैं। इसके अलावा विभिन्न पर्वों पर ज्वार के आटे के पकवान पूड़ी, पुआ आदि बनाए जाते हैं। ज्वार का आटा बेहद पौष्टिक माना जाता है। ज्वार में मूलतः तना छेदक कीट और दीमक रोग लगता है। तना छेदक और दीमक के प्रकोप से नष्ट हो जाता है। दीमक भुट्टे को प्रभावित करता है। साथ ही तनों की जड़ों को भी कमजोर कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए कारबोराइल 50 प्रतिशत, घुलनशील चूर्ण को 1.25 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500-700 लीटर पानी में घोलकर छिडकाव करना चाहिए। ज्वार की फसल की बुआई से किसानों के द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कृषि विभाग से संबंधित प्रभारी सरकारी बीज भंडार खागा जितेन्द्र सिंह ने बताया कि लगभग पांच वर्षो से विभाग से ज्वार का बीज नहीं मिल पा रहा है। अब इसके बीज के लिए किसान भी नही आते हैं।

तेंदुली गांव के युवक को हाईवे किनारे मिली नवजात बच्ची

■ बच्ची की हालत गंभीर देख सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर ■ सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस किया छानबीन

बिन्दकी, फ्तेहपुर । तेंदुली गांव निवासी एक युवक को कानपुर से अपने घर आते समय रास्ते में हाईवे किनारे झाड़ में एक नवजात बच्ची पड़ी मिली तो उसने बच्ची को उठा लिया अपने घर लाए उसने इस मामले की सूचना पुलिस को दी पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने पहुंची वहीं बच्ची की हालत नाजुक देख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जहां से चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव निवासी ज्ञान प्रकाश तिवारी अपने निजी वाहन से कानपुर से अपने घर आ रहे थे वह छिवली नदी के समीप लघुशंका के लिए ठहरे तो उनकी नजर झाड़ में पड़ी तो देखा कि एक नवजात बच्ची रूबी लग रही है उन्होंने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और लेकर अपने घर आए उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को भी दी पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन किया उधर बच्ची की हालत चिंताजनक देख उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया महिला चिकित्सकों ने भी बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली हालत सही ना होने पर उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

नवजात बच्ची उपचार हेतु भर्ती

फ्तेहपुर । चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना प्राप्त हुई कि जिला चिकित्सालय फ्तेहपुर में अज्ञात नवजात बच्ची है जिस पर चाइल्ड लाइन टीम मौके पर पहुंचकर कॉलर से मुलाकात की, जिससे पता चला कि बिंदकी कोतवाली अंतर्गत ग्राम तेंदुली निवासी संतोषी तिवारी पत्नी ज्ञान प्रकाश तिवारी जो अपना इलाज करा कर कानपुर से लौट रहे थे तभी उनके पति लघूशंका हेतु रुके तभी बच्ची के रोने की आवाज जीटी रोड के किनारे सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा एक पॉलिथीन में लिपटा हुआ शिशु रो रहा है जिसे लेकर उन्होंने सूचना कोतवाली पुलिस बिंदकी को दी। कोतवाली पुलिस के सहयोग से बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी ले गए, जहां से बच्ची जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दी गई गई। जिला अस्पताल आने के उपरांत चाइल्ड लाइन 1098 को सूचना दी गई तब चाइल्डलाइन द्वारा बच्ची को अपनी सुपुर्दगी में लेकर न्याय पीठ बाल कल्याण समिति को एवं विशेष पुलिस इकाई को सूचना दिया गया और जिला अस्पताल में भर्ती किया गया जिसका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है।

घर से गायब हुई महिला के बच्चे व पति है परेशान

जहानाबाद, फ्तेहपुर । थाना क्षेत्र के ग्राम नसेनिया निवासी एक युवक ने बताया 25 दिनों से उसकी पत्नी गुमशुदा है जिस की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहा हूं। जानकारी के अनुसार उक्त क्षेत्र के ग्राम निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मेरी पत्नी पिंकी देवी विगत 31 जुलाई को दोपहर अपने मासूम बच्चों को छोड़कर घर से अचानक लापता हो गई थी। जिस पर पीड़ित ने आज थाना जहानाबाद पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। महिला 25 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं पहुंची जिससे उसके मासूम बच्चे अपनी मां को याद कर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वही उसका पति अपनी पत्नी की तलाश पर दर-दर की ठोकरें खाता नजर आ रहा है। पीड़ित ने बताया 25 दिनों के बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस तथा उसकी तलाश को कामयाबी नहीं मिल सकी है तब उसने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गुमशुदा महिला की तलाश पर जल्द से जल्द सुराग लगाने का गुहार लगाई है। थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष शर्मा ने बताया युवक की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। महिला की तलाश हेतु जगह जगह सुराग लगाए जा रहे हैं।

धाता क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शीघ्र मिलेगी लो-वोल्टेज की समस्या से निजात

धाता, फ्तेहपुर । अटेलवा विद्युत उपकेंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं को जल्द ही लो बोल्टेज की समस्या से निजात मिलने वाली थी, लेकिन एक सप्ताह से हो रही लगातार बरसात के कारण काम में बाधा के चलते मशीनें नहीं बदली जा सकीं। उपकेंद्र पर आठ एमबीए का ट्रांसफार्मर बदलकर दस एमबीए का ट्रांसफार्मर रखा जाना था। ट्रांसफार्मर उपकेंद्र पर पहुंच गया है। थाना क्षेत्र के अटेलवा उपकेंद्र से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को इस समय लो बोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस उपकेंद्र पर धाता, सोनारी जाम के नाम से तीन फीडर हैं। इनसे लगभग एक सैकड़ा से ज्यादा गांव के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है। बताया जाता है कि यहां पर एक आठ एमबीए का ट्रांसफार्मर है। उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने और ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से उपभोक्ताओं को बिजली समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। अब उपकेंद्र पर एक और दस एमबीए का ट्रांसफार्मर रखा जाएगा। उपकेंद्र पर दस एमबीए का नया ट्रांसफार्मर पहुंच गया है।

अधिकारियों ने माने तो इस हफ्ते के अंदर ही दूसरा ट्रांसफार्मर रख दिया जाता इसको लेकर उपभोक्ताओं में खुशी देखी जा रही थी। धाता क्षेत्र के अटेलवा उपकेंद्र से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को इस समय लो बोल्टेज की समस्या का कभी कभी सामना करना पड़ जाता है। इस उपकेंद्र पर धाता, सोनारी जाम के नाम से तीन फीडर हैं। इनसे लगभग एक सैकड़ा से ज्यादा गांव के लिए बिजली आपूर्ति की जाती है। बताया जाता है कि उपकेंद्र से लगभग दस हजार बिजली उपभोक्ता जुड़े हैं। बिद्युत उपकेन्द्र में लगे 05 व 08 एमबीए के ट्रान्सफार्मर लगे थे जिससे ओवरलोडिंग के चलते सही बिजली क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रही थीं। 10-10 एमबीए के दो ट्रान्सफार्मर और आउट गोइंग इनकमिंग आदि मशीने उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने और ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से उपभोक्ताओं को बिजली समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू कर दी थी। अब उपकेंद्र पर दस एमबीए का ट्रांसफार्मर रखा जाना था। उपकेंद्र पर दस एमबीए का नया ट्रांसफार्मर पहुंच गया था। बीते रविवार से ही 10-10 एमबीए के दो ट्रान्सफार्मर आउट गोइंग इनकमिंग आदि मशीने बदलने का काम चल रहा था, लेकिन ज्यादा बरसात हो जाने से विद्युत उपकेंद्र मे पानी ही पानी भर गया जिससे काम बाधित हो गया। जैसे ही परिसर का पानी सूख जाएगा शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जाएगा। अवर अभियंता चंद्रमा प्रसाद यादव का कहना कि बरसात होने पर पूरे विद्युत परिसर मे पानी भर जाने पर काम बाधित हो गया है जो पानी सूखने के साथ ही तत्काल चालू कर दिया जाएगा।

मोहर्रम को लेकर सहादत गंज कोतवाली का औचक निरीक्षण करने पहुंचे जेसीपी नवीन अरोड़ा व डीसीपी पश्चिम सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी व अन्य।

कोविड-19 चिकित्सालय के रूप में मंडल स्तर पर हुई कुल 1778 कोविड-19 जांचें

लखनऊ, संवाददाता। जैसा कि ज्ञात है कि कोविड-19 महामारी से सुरक्षा एवं बचाव संबंधी प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय लखनऊ को स-1 श्रेणी हेतु नामित किया गया है, इस श्रेणी में कोविड-19 के (सामान्य लक्षण) मरीज चिकित्सालय में भर्ती किये जा रहे है, 250 बेडो की क्षमता वाले इस चिकित्सालय में 237 बेड स-1 श्रेणी के है तथा शेष 13 बेड स-2 श्रेणी के मरीजो हेतु उपलब्ध है, मंडल के समस्त चिकित्सक ,पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य मेडिकल स्टाफद्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से रोगियों के रोग के उपचार की एक व्यवस्था स्थापित की गयी हैप्चिकित्सा विभाग की टीम पूर्ण मनोयोग से अपने सम्मिलित प्रयासों द्वारा अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाओं का प्रदर्शन कर रही है, इसी क्रम में मंडलीय चिकित्सालय में रेलकर्मियों

का पद्धति से सैंपल लेकर जांच हेतु किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा जाता है।

जांच की रिपोर्ट के आधार पर सम्बंधित कर्मचारी हेतु कोविड-19 संबंधी प्रोटोकाल अपनाते हुए आवश्यक चिकित्सा प्रणाली अपनाई जाती है, ये जांच प्रक्रिया दिनांक-04.04.20 से निरंतर अमल में लायी जा रही है एवं इसके अन्तर्गत दिनाक-24.08.20 तक की अवधि में कुल 1212 कर्मियों का सैंपल लेते हुए अग्रिम चिकित्सा कार्यवाही निर्धारित की गयी,इसके अतिरिक्त मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर राज्य सरकार के सहयोग से दिनांक 07.07.20 से दिनांक-24.08.20 की अवधि तक कुल 566 रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किये हैं, इस विषय में मंडल रेल प्रबंधक संजय त्रिपाठी ने अवगत कराया कि कोविड-19 हेतु नामित मंडलीय चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं अन्य मेडिकल स्टाफ द्वारा कोविड-19 के रोगियों की चिकित्सा हेतु रोगियों का गहन निरीक्षण करते हुए निरंतरता के साथ परीक्षण तथा चिकित्सा कार्य किया जा रहा है, मंडल के चिकित्सा विभाग के समस्त चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी दिन-रात अपने अथक प्रयासों द्वारा अपनी श्रेष्ठतम सेवाओं को सम्पादित कर रहे हैं एवं रोगियों को त्वरित उपचार के साथ ही परिसर की सम्पूर्ण स्वच्छता को रखते हुए गुणवत्ता पूर्ण आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है और डाक्टरो द्वारा व्यक्तिगत रूप से रोगियों के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

योगी ने दिए कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 का चिकित्सा जांच कार्य पूरी क्षमता से संचालित करने के मंगलवार को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को गुणवत्तापरक बनाकर रखा जाए। उन्होंने जनपद कानपुर नगर, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा बलिया में विशेष सतर्कता बरतने तथा अधिक से अधिक टेस्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में कारगर रणनीति तैयार करते हुए उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नियंत्रण व उपचार

सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को सुचारु ढंग से संचालित करने में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। बेहतर सर्विलांस ही मृत्यदर को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेण्टर के कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं को गुणवत्तापरक बनाए रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ नियमित राउण्ड लें। चिकित्सा के तकनीकी स्टाफ में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाए। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को मेडिकल संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए इनके प्रशिक्षण कार्य को निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ऑनलाइन ओ0पी0डी0 सेवा 'ई-संजीवनी' अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है। बड़ी संख्या में मरीज इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि 'ई-संजीवनी' सेवा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऑनलाइन ओ0पी0डी0 सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने डोर-टू-डोर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टीमें लगाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्याप्त मात्रा में खाद की व्यवस्था की है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को समय से खाद मिलती रहे तथा खाद की कालाबाजारी न होने पाए। यदि कहीं भी खाद की कालाबाजारी हो तो इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ एन0एस0ए0 के तहत कार्यवाही की जाए।मुख्यमंत्री ने गोवंश की नस्ल सुधार का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा संतति (बछिया) होंगी।

सीएम की वायरल ऑडियो पर डीएम वाराणसी का नोटिस अवैध

लखनऊ, संवाददाता। एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने वाराणसी के व्यापारी नेता राकेश जैन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत के ऑडियो के वायरल करने पर डीएम वाराणसी कौशल राज शर्मा द्वारा उन्हें इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 5(2) तथा 26 सहित अन्य कानून में जारी नोटिस को कानूनी रूप से अवैध बताया है। मुख्यमंत्री तथा डीएम वाराणसी को भेजे पत्र में नूतन ने कहा कि टेलीग्राफ एक्ट का संबंध फोन टैपिंग या इंटरसेप्शन से है एवं इस एक्ट की धारा 26 मात्र टेलीग्राफ विभाग के कर्मियों पर लागू होती है. अतः इस एक्ट के प्रावधान बातचीत के क्रम में स्वतः हुई रिकॉर्डिंग पर लागू नहीं होते हैं और न ही ऐसा कोई कानून है जिसमे रिकार्डेड फोन को सार्वजनिक करना अपराध हो। नूतन ने कहा कि जब उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह से बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक किया था।

ईद की नमाज की तरह अन्य धार्मिक समारोहों में सावधानी बरती जानी चाहिए

लखनऊ, संवाददाता। मुस्लिम उम्मा को सावधानी बरतनी चाहिए और ईद-उल-फित्र और शुक्रवार जैसे अन्य धार्मिक समारोहों में भूमि के नियमों का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद आफाक ने आज यहां कहा कि हमें भावुक नहीं होना चाहिए और देश और राष्ट्र को भारी घाटे और परेशानी में डालना चाहिए। मोहर्रम समारोह के संबंध में संगठन के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए, उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने आस-पड़ोस के लोगों को पछाड़ने के लिए नहीं बल्कि सामाजिक दूरी के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने के लिए कहें। उन्होंने कुछ लोगों की आलोचना की जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और इस संबंध में सिट-इन और प्रदर्शनों की धमकी दे रहे थे। मस्जिदों में पांच दैनिक प्रार्थनाएं पेश की जा रही हैं। हमें उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए अन्य धार्मिक समारोह करना चाहिए।

अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

लखनऊ, संवाददाता। लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट द्वारा मुकदमों की ई-फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के लिए की गई व्यवस्था से तमाम वकील असंतुष्ट हैं। मंगलवार को अधिवक्ता इसके विरोध में हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 के सामने धरना करने लगे। अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में फिजिकल सुनवाई को लेकर अड़े हुए थे। अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आरोप था कि हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था की है, वह सुचारु रूप से काम नहीं कर रही है। जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ देर तक धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से उनकी बात सुनने कोई नहीं आया, तो वकीलों ने अपनी शिकायतें और मांगें लिखित रूप से महानिबंधक के पास भिजवा दी। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो वह बुधवार को फिर से प्रदर्शन करेंगे। हाईकोर्ट ने 11 और 14 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर मुकदमों की ई-फाइलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई का निर्देश दिया है। मंगलवार को मुकदमों की फाइलिंग करने पहुंचे वकीलों की शिकायत थी कि अर्जेंसी में वे जो मुकदमे दाखिल कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कोड नहीं भेजा जा रहा है। ई-फाइलिंग सेंटर पर मुकदमों का दाखिला भी सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है। जो याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, उन पर डिफेक्ट लगा दिया जा रहा है। वहीं, कुछ याचिकाएं दाखिल होने के बावजूद सूचीबद्ध नहीं हो रही हैं। अधिवक्ताओं का कहना था कि हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई होने की जानकारी होने पर वादकारी उन पर दबाव बनाते हैं। अधिवक्ता कोर्ट बंद होने से आर्थिक रूप से भी परेशान हैं।

रतन सिंह हत्याकाण्ड की निष्पक्ष जॉच स्पेशल टीम गठित करके करायी जायः प्रमोद तिवारी

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीएम योगी को पत्र लिख कर मांग की है मुख्यमन्त्री जी दिनांक- 24 अगस्त, 2020 को जनपद बलिया के थाना फेफना के अंतर्गत हिन्दी न्यूज चौनल सहारा के पत्रकार रतन सिंह की निर्ममता पूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गयी। रतन सिंह की हत्या थाना फेफना से चन्द कदम की दूरी पर की गयी है। पूर्व में इनके परिवार में घटना हो चुकी थी जो प्रशासन की जानकारी में थी तो पत्रकार रतन सिंह की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किये गये थे ? अवगत कराना है कि अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलन्द हो गये हैं कि अब लोकतन्त्र के ''चौथे स्तम्भ'' पत्रकारिता पर भी वे बेखौफहोकर हमले कर रहे हैं। कई पत्रकारों की नृषंसतापूर्वक हत्या की जा चुकी है, तथा कई पत्रकारों पर गम्भीर हमले किये गये है, पत्रकारों के उनके उत्पीड़न की घटनायें आम होती जा रही है। अपराधियों में शासन- प्रषासन का तनिक भी भय नहीं रहा, और वे निडर होकर पत्रकारिता पर दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेरा आग्रह है कि कृपया रतन सिंह, जो एक निर्भीक और निष्पक्ष आवाज उठाने वाले पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, उनके परिवार को मुआवजे के रूप में रु. 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। तथा रतन सिंह हत्याकाण्ड प्रकरण की निष्पक्ष जॉच एक स्पेशल टीम गठित करके करायी जाय।

ज्ञान यज्ञ ही युगधर्म हैः उमानंद शर्मा

लखनऊ, संवाददाता। गायत्री ज्ञान मंदिर इंदिरा नगर, लखनऊ के विचार क्रान्ति ज्ञान यज्ञ अभियान के अन्तर्गत फिरोज गाँधी डिग्री कालेज, रायबरेली के पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युगऋषि पं0 श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सम्पूर्ण 79 खण्डों का वांड्मय साहित्य की स्थापित किया गया। उपरोक्त यह वाड्मय साहित्य गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, गायत्री ज्ञान मंदिर इन्दिरा नगर के सक्रिय कार्यकर्ती श्रीमती रेखा सिंह ने अपनी पुत्री शिवा सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उज्जवल भविष्य की कामना में संस्थान के पुस्तकालय को भेंट की। इस अवसर पर वाड्मय स्थापना अभियान के मुख्य संयोजक उमानंद शर्मा वाड्मय साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ''ज्ञान यज्ञ ही युगधर्म है। इसमें सभी जीवित जाग्रत आत्माओं को भाग लेना चाहिये।

सफाई कर्मचारी संघ की बैठक हुई संपन्न

चार चरणों की बैठक मे प्रथम चरण की बैठक हुयीं

लखनऊ, संवाददाता। आज को लोक निर्माण विभाग लखनऊ मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के कार्यालय सभागार में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक मे कोरोना को देखते हुए सभी को सेनीटाइज तथा शोशल डिस्टेस का पूरा ध्यान रखा गया,बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए निदान कराए जाने हेतु सहमति बनी, सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर पदोन्नति सफाई कर्मचारियों के पदनाम को परिवर्तित कर पंचायत सेवक किया जाए,कोविड-19 में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के द्वारा पिछले 5 महीनों से बिना किसी अवकाश के लगातार कार्य किया जा रहा है सासाहिक अवकाश घोषित किया जाये,दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को तत्काल एसीपी का लाभ प्रदान किए जाने हेतु आदि मुख्य मांगों पर उपस्थित संघ के जिला स्तरीय एवं प्रदेश पदाधिकारी सहमति प्रदान की,संघ के प्रदेश महामंत्री रामेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित करते हुए उपस्थित सदस्यों को आश्वासन दिया की जल्द ही शासन प्रशासन में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को उच्चाधिकारियों के पटल पर रखा जाएगा और समय रहते समस्याओं का निदान कराया जाएगा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने बैठक को सम्बोधित करतें हुयें कहा की प्रदेश मे सफाई कर्मचारियों को शोषण हो रहा जिसे अब बर्दाश्त नही किया जायेगा सफाई कर्मचारी की मांग नही मानी गयीं तो जल्द ही बडा आन्दोलन होगा सफाई कर्मचारियों की जनपद स्तर पर कोई समस्याओं का निराकरण नही हो रहा हैं।

कानपुर पुलिस लाइन हादसा, 1 करोड़ मुआवजा सहित अन्य मांग

लखनऊ, संवाददाता। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कल कानपुर नगर के पुलिस लाइन्स के बैरक की छत गिरने से सिपाही अरविन्द सिंह की मौत तथा तीन अन्य सिपाहियों के घायल होने के मामले में मृतक सिपाही के परिवार को सेवा संबंधी अन्य देयक के साथ सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये तथा घायलों को 5-5 लाख का मुआवजा दिए जाने का अनुरोध किया है। अपर मुख्य सचिव गृह तथा डीजीपी, यूपी को भेजे अपने पत्र में अमिताभ ने कहा कि सामने आई जानकारी अनुसार इस बैरक के जर्जर होने की कई बार शिकायत की गयी किन्तु इन शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया इन स्थितियों में लापरवाही हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पर कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होगा।

लखनऊ में करना हो बिना मानचित्र अवैध निर्माण तो सरकारी दफ्तर में एलडीए बाबू समझ लीजिए

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ में बिना मानचित्र धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को सरकारी दफ्तर में एलडीए बाबू समझ रहे हैं। इस बात की पुष्टि कुर्सी रोड पर बिना मानचित्र अवैध निर्माण करा रहे मकान मालिक ने कही। उसने साफकहा कि एलडीए का एलडीए के बाबू आरपी से बात हुई थी। वहीं बिना मानचित्र निर्माण कराने का काम सुशील यादव द्वारा कराया जा रहा है। एलडीए के जिसके बाद अवैध निर्माण का कार्य बेरोकटोक किया जा रहा है। इसकी शिकायत जोन पांच के प्रवर्तन अधिकारी के के बंसला को भी हुई। बंसला ने जोनल अभियंता को कार्रवाई के आदेश दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला विकास नगर थाना क्षेत्र के कुर्सी रोड पर सब्जी मंडी के पास हो रहे अवैध निर्माण का है। एलडीए के कर्मचारियों की मदद से यहां बिना मानचित्र ही दो मंजिला कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। मामला पूरी तरह एलडीए की जानकारी में होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि मंगलवार सुबह प्रवर्तन अधिकारी के के बंसला ने साइट इंजीनियर को कार्रवाई के आदेश दिए लेकिन मामला सिफर रहा। के के बंसला प्रवर्तन अधिकारी जोन पांच का कहना है कि, क्षेत्रीय अभियंता को कार्य रुकवाने के आदेश दिए गए हैं, बिना मानचित्र निर्माण कराए जाने पर जांच कर बिल्डिंग को सील किया जाएगा।

मामूली विवाद में हुआ गोली व बम से हमला

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ में बेखौफहो चुके बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। जहां देर रात जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट में बदमाशों को गाड़ी खड़ी कर दारू पीने को मना करने पर उन्होंने एकाएक फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों का मन इससे भी नहीं भरा तो घर पर शुतली बमों से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 खोखे भी बरामद किए हैं। बदमाशों के इस जानलेवा हमले में फिलहाल कोई भी घायल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट में देर रात पेशे से अधिवक्ता राजा सिंह के ऊपर देर रात पवन, पीयूष धन्ने व ईशु सोनी ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर फायरिंग व बम से जानलेवा हमला कर दिया। फायरिंग व बम से हमला होने के दौरान आस-पास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी बदमाश मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच करने के साथ ही बदमाशों की तलाश में जुटी है।

यूपी में पूरी तरह से चरमरा गई है कानून व्यवस्थाः मायावती

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि यूपी में अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां आए दिन हर प्रकार के अपराध देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में भाजपा के शासन से लोग दुखी हो गए हैं। अब सपा-भाजपा के शासन में कोई अंतर नहीं रह गया है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां आए दिन हत्या व जुर्म के शिकार हो रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में हुई पत्रकार की हत्या इसका ताजा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में सरकार की बदहाली का हाल ये है कि बात-बात पर रासुका, देशद्रोह व अन्य अति

संगीन धाराओं के इस्तेमाल के बावजूद भी यहां अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मायावती ने कहा लोगों को अब मेरा शासन याद आ रहा है। प्रदेश में कानून का जातिगत इस्तेमाल हो रहा। कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सरकार से लोग दुखी थे। कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो। मेरे लिए हर जगहों पर जाना मुश्किल। बीएसपी नेता घटनास्थल पर जाएंगे। गरीब, कमजोर वर्ग के लोगों में बदलाव नहीं हुआ। एसपी शासन काल में गुंडों का राज था। कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं। परीक्षाओं पर केंद्र व राज्य सरकार जरूरी कदम उठाएं। परीक्षा करवाने की उचित व्यवस्था हो। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो। देश के ज्यादातर सरकारी स्कूल बंद है।

पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर यूपी सरकार का रवैया निंदनीयः प्रियंका गांधी

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश की योगी सरकार पर पत्रकारों की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता को लेकर उसका रवैया निंदनीय है। वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा देने में यह सरकार असफल साबित हो रही है और

इसी का परिणाम है कि पिछले तीन माह के दौरान हर माह एक पत्रकार की हत्या हो रही है। प्रशासन खुद पत्रकारों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इसी का परिणाम है कि खबर लिखने पर राज्य में लगातार पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उन्होंने राज्य में पत्रकारों की हत्या की तारीख देते हुए ट्वीट किया और कहा ''19 जून- श्री शुभममणि त्रिपाठी की हत्या, 20 जुलाई- श्री विक्रम जोशी की हत्या, 24 अगस्त- श्री रतन सिंह की हत्या, बलिया। पिछले तीन महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या। ग्यारह पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते प्राथमिकी दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतन्त्रता को लेकर ये रवैया निंदनीय है।

सृजन सेवा रथ-अम्मा बब्बा की रसोई का उदघाटन, 10 रुपये में मिलेगा खाना

लखनऊ, संवाददाता। कोविड 19 के इस विपदा वाले दौर में सृजन फाउंडेशन द्वारा 25 मार्च, 2020 से जून प्रथम सप्ताह तक निरंतर जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन उपलब्ध कराया गया। कोई न सोये भूखे पेट मुहिम के अंतर्गत यह सारा कार्य किया गया। यह उदघाटन सृजन फाउंडेशन के संरक्षक मनोज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर दिलीप यशवर्धन, क्षमा जायसवाल, सुनील वर्मा, परमेश गर्ग, शंभुशरण वर्मा, कुश श्रीवास्तव, मोहित श्रीवास्तव, डॉ अमित सक्सेना आदि उपस्थित रहे। स्नेहधरा वृद्धाश्रम के डायरेक्टर अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि इस सेवा रथ के माध्यम से निराश्रित जनों के लिए निःशुल्क एवं अन्य लोगों के लिए श्रम सेवा के लिए 10 रुपये सहायतार्थ राशि में खाना (चावल-छोला,राजमा,कढ़ी, हलवा,बूंदी, सलाद) उपलब्ध कराया जाएगा। आज उदघाटन पर लोगों को छोले-चावल, हलुआ, सलाद उपलब्ध कराया गया। साथ ही गिलोय वाली चाय भी दी गयी।

यूपी के सीएम पर जातिवादी राजनीति करने के आरोप गलतः सुखबीर सिंह

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार पर आम आदमी पार्टी द्वारा एक वर्ग विशेष जाति की राजनीति करने के आरोपों को निराधार बताते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सुखबीर सिंह भदौरिया ने राजधानी लखनऊ के प्रेसक्लब पत्रकार वार्ता करके सभी आरोपो पर विराम लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व प्रदेश प्रभारी व अन्य दलो के ब्राह्मण नेता राजनीतिक लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर अनर्गल आरोप लगाकर क्षत्रिय समाज को अपमानित कर रहा हैं। श्री भदौरिया ने उन्हे नसीहत दी किआप के संजय सिंह सहित अन्य कथित ब्राह्मण नेताओ कोजाति धर्म समुदाय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भुवनेश्वर सिंह ने कहा कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जम्मू में आयोजित होने वाली महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूरे प्रदेश में केसरिया निकाली जाएगी।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एक सार्थक पहल

पिछले सत्तर सालों में देश की तमाम समस्याओं में बेरोजगारी भी शामिल है। सरकारी व प्राईवेट सेक्टर में नौकरियां मांग के हिसाब से काफी कम है। सरकारी नौकरी भले ही वो केंद्र की हों या प्रदेश सरकार की नौकरी चाहने वालों की पहली पसंद रहती है। लेकिन सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता और लेटलतीफी बड़ी समस्या है। बदलते दौर में नौकरियों का स्वरूप बदला है तो वही भर्ती के तरीके भी बदले हैं। बी और सी समूह के गैर तकनीकी पदों के लिए केंद्रीय सेवाओं में रोजगार देने की दिशा में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब तीन करोड़ युवा सरकारी नौकरियों के लिए हर साल परीक्षाएं देते हैं। निस्संदेह भर्ती प्रक्रिया में सुधार का लाभ उन्हें मिलेगा। यह कदम देश में राष्ट्रीय स्तर की रिक्तियों में चयन के लिए परीक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दरअसल, अब तक देश में लगभग बीस भर्ती एजेंसियां प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करती रही हैं। इनके केंद्र भी अलग-अलग स्थानों पर निर्धारित होते थे, जिसके चलते कई बार परीक्षार्थियों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। कई बार परीक्षार्थियों की संख्या का इतना दबाव होता था कि उन्हें रेलगाड़ी अड़ैर बसों की छत में बैठकर सफर तय करना पड़ता था। फिलहाल सरकार ने तीन प्रमुख एजेंसियों- कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड तथा बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान को ही राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की साझा पात्रता परीक्षा में शामिल किया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शीघ्र ही अन्य बड़ी एजेंसियां इसमें शामिल हो सकें। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के क्रियान्वयन के लिए पंद्रह हजार करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की है। केन्द्र सरकार का यह फैसला जमीन पर कितने बदलाव लाएगा, ये अभी ज्यादा लोगों का समझ नहीं आ रहा है। वास्तव में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का लाभ देश के करोड़ों परीक्षार्थियों को मिल सकेगा, क्योंकि अब वे एक ही परीक्षा पास करके कई पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ?ही आवेदकों को बार-बार आवेदन करने और ?फीस भरने के झंझट से निजात मिलेगी। इस एजेंसी के गठन से बैंक और रेलवे सहित केंद्र सरकार एवं बैंक जैसे सार्वजनिक उद्यमों में बी और सी समूह के गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु एक ही प्रवेश परीक्षा होगी जिसे पास करने के बाद अपने इच्छुक विभाग की अंतिम परीक्षा में बैठा जा सकेगा। अच्छी बात ये रहेगी कि फाइनल परीक्षा में फेल होने के बाद दोबारा प्रवेश परीक्षा से मुक्ति मिल जायेगी। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना एक तरह से प्राथमिक योग्यता मानी जायेगी। अभी विस्तृत विवरण आना बाकी है। सबसे खास बात यह है कि अब रोजगार चाहने वालों को परीक्षा देने के लिए दूरदराज के शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और तमाम दूसरी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेगी। योजना के मुताबिक अब पूरे देश में एक हजार से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाये जायेंगे। कोशिश होगी कि हर जिले में एक परीक्षा केंद्र हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि साझा पात्रता परीक्षा युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। निश्चित रूप से इस प्रयास से बेरोजगारों के समय व धन की बचत होगी। इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। वर्तमान में, उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा। इससे महिला अभ्यर्थियों को भी काफी राहत मिलेगी क्योंकि कभी-कभी उन्हें इन दूरस्थ स्थानों पर स्थित इन केंद्रों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है। प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को अधिक लाभ होगा। परीक्षा हेतु पंजीयन भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस बारे में उल्लेखनीय है कि अतीत में महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से भर्ती परीक्षा में आये परीक्षार्थियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इन अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं से उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ पड़ता है। इसमें बार-बार होने वाले खर्च, कानून और व्यवस्थाध्सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं। औसतन, इन परीक्षाओं में अलग से ढाई से तीन करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। साझी पात्रता परीक्षा (सीईटी) उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे तथा उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाएगी। आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इस परीक्षा में हासिल स्कोर तीन साल तक मान्य होंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग-अलग महकमों द्वारा समान पद हेतु की जाने वाली भर्ती के लिए अलग-अलग परीक्षा लिए जाने से बेरोजगारों पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ता है। अपने घरों से दूर परीक्षा हेतु जाने के लिए अनेक के पास पैसे तक नहीं होते। और फिर परीक्षा की समय-सारिणी कब बदल जाए ये कहना कठिन है। कुल मिलाकर अलग-अलग भर्ती परीक्षाएं भारत के संघीय ढांचे के भी अनुरूप नहीं हैं। इससे विभागों द्वारा अलग-अलग परीक्षाओं पर होने वाले खर्च की भी बचत हो सकेगी। परीक्षा के परिणाम भी जल्दी आयेंगे जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न नौकरियों में अपनी पसंद चुनने का बेहतर अवसर मिल सकेगा। केंद्र सरकार का ये कदम प्रशासनिक सुधार के साथ ही पारदर्शिता बढाने वाला भी होगा। जमीनी सच्चाई यह है कि देश में प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को तमाम परीक्षाओं के लिए अलग-अलग फीस भरनी पड़ती थी और दूर-दराज के इलाकों में परीक्षा देने के लिए आवागमन में खर्च भी करना पड़ता था जो बेरोजगारी के दौर में उनकी मुश्किलों को ही बढ़ाता था। देर से उठाये गये इस कदम का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन बेरोजगार युवाओं के लिए राहत का सबब बन सकता है। देश में बेरोजगारी की भयावह स्थिति के कारण बहुत बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो अलग-अलग परीक्षाओं के कारण परेशान हो गये हैं। इस एजेंसी को मूर्तरूप लेने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। देश भर के जिलों में केंद्र खोलकर परीक्षा का आयोजन भी आसान काम नहीं होगा। लेकिन इस फैसले को एक बड़े सुधार के तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद करना गलत नहीं होगा। लेकिन केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि एजेंसी का काम निश्चित समय सीमा में सम्पन्न हो क्योंकि हमारे देश में सुधारवादी फैसले लिए जाने के बावजूद उन्हें अमल में लाने का काम मंथर गति से होने के कारण उनकी उपयोगिता और प्रभाव दोनों नकारात्मक हो जाते हैं। एक देश एक भर्ती परीक्षा का निर्णय राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेगा, और देश के साधनों और संसाधनों की भी बचत के साथ भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता भी आएगी।

सम्पादकीय
कांग्रेस की दशा-दिशा

तेइस वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पार्टी संगठन में बदलाव की मांग को लेकर लिखे पत्र के लीक होने के बाद कांग्रेस में जो सतही घमासान दिखायी दे रहा है, वह भले ही वास्तविक हो या रणनीति का हिस्सा, उससे पार्टी का भला ही होने जा रहा है। वर्ष 2018 में तीन राज्यों में शानदार जीत के बावजूद पार्टी को इतनी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिल पायी थी, जितनी इस विवाद से मिली। पिछले कुछ दिनों में पार्टी में एकता और सोनिया गांधी से स्थायी नेतृत्व संभालने को लेकर जो मुहिम जारी रही, उसके निहितार्थ इससे कुछ अलग नहीं हैं। सोमवार को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैराथन बैठक में सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद संभाले रखने और अगले छह माह में नये अध्यक्ष के चुनाव के लिये एआईसीसी की बैठक बुलाने का निर्णय किया गया। सोमवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के बीच विरोध करने वाले नेताओं की भाजपा से सांठगांठ पर राहुल गांधी के कथित बयान के उल्लेख और उस पर वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया को शाम होते-होते मीडिया की उपज करार दे दिया गया। फिर इन नेताओं के भी पार्टी नेतृत्व के समर्थन वाले बयान सामने आने लगे। विरोध करने वाले नेताओं ने अपने ट्वीट वापस ले लिये। दरअसल, कांग्रेस कार्यसमिति की सोमवार को हुई बैठक पार्टी के 23 दिग्गज नेताओं के सोनिया गांधी को लिखे पत्र के लीक होने के बाद के हालात पर विचार-विमर्श करने के बाबत आहूत की गई थी। इस पत्र पर गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण, आनन्द शर्मा जैसे दिग्गजों के हस्ताक्षर बताये जाते हैं, जो पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान रहे हैं। गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान रहे इन नेताओं के पत्र को लेकर कयास लगाये जाते रहे हैं कि क्या वाकई ये पार्टी की साख में आ रही गिरावट को देखते हुए बदलाव के मकसद से लिखा गया या फिर नेतृत्व परिवर्तन के लिये गांधी परिवार के अनुकूल वातावरण तैयार करने को लेकर लिखा गया। बहरहाल, हालिया विवाद ने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या वाकई पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर मतभेद हैं? क्या पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की संभावना है? क्या फिलहाल कांग्रेस में गांधी परिवार के बिना नेतृत्व की संभावना है? क्या वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति के मद्देनजर राहुल गांधी द्वारा बदलाव के लिये दिये गये इस्तीफे की मंशा को पूरा किया जा रहा है? क्या मौजूदा मुहिम राहुल गांधी की ताजपोशी के लिये आधारभूमि तैयार कर रही है? सोमवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी से अगले निर्णय तक अध्यक्ष पद पर बने रहने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया। दरअसल, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद ऐसी ही मुहिम चला रहे थे। सांसदों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी। साथ ही आग्रह किया था कि जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं संभालते तब तक वे अध्यक्ष बनी रहें। साथ ही यह भी आरोप लगाया जाता रहा है कि जो लोग नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वे भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। इस मुहिम से जाहिर था कि पार्टी के नेता व कार्यकर्ता गांधी परिवार के नेतृत्व को ही मजबूत करने की बात कर रहे थे। वह भी ऐसे समय में जब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी के कार्यकाल को एक वर्ष पूरा हो चुका है। कयास लगाये जा रहे हैं कि यह समय राहुल गांधी को अपनी टीम तैयार करने के लिये दिया जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की सोच है कि पार्टी की एकता गांधी परिवार के हाथों ही संभव है। इसके बावजूद पार्टी में अनुभवी व बड़े कद के नेताओं की कमी नहीं है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब कोई पार्टी मुश्किल वक्त से गुजर रही हो तो पार्टी में अंतर्विरोध के स्वर स्वाभाविक हैं।

स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी पहल

सचमुच जादुई बात लगती है. आपके पास एक निश्चित नंबर वाला छोटा-सा पुर्जा हो और आप अपनी या परिजन की जान जल्दी से जल्दी बचाने का इंतजाम कर लें. अभी नंबरवाला कागज न होने के कारण बीमारियों से अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. कितने ही लोग दिल्ली या मुंबई में 25 से 50 लाख रुपयों के खर्च से पांच सितारा अस्पताल में ऑपरेशन और इलाज के बाद, किसी अन्य शहर या विदेश में जाकर बीमार हो जाएं, तो समुचित रिकॉर्ड नहीं होने से स्वास्थ्य के नये संकट का सामना नहीं कर पायेंगे. ऐसे हालात से निबटने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र योजना के सही ढंग से क्रियान्वित होने पर सामाजिक स्वास्थ्य की नयी क्रांति हो सकेगी. यह केवल राजनीतिक वायदा या भाषणबाजी नहीं है. महीनों के उच्च स्तरीय विचार-विमर्श तथा तैयारियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प के साथ इसकी घोषणा की है. कुछ हफ्तों पहले सरकार ने नयी शिक्षा नीति की घोषणा भी कर दी है. हाल के वर्षों में भारत के श्रेष्ठतम डॉक्टरों ने दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायी और दूसरी तरफसरकारी आयुर्विज्ञान संस्थान के अलावा निजी क्षेत्र में भी अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित हुए. निजी हों या सरकारी, सबसे गंभीर समस्या रही है कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने या देश-विदेश में दोबारा स्वास्थ्य समस्या आने पर व्यक्ति के पास केवल कुछ कागज और रिकॉर्ड होते हैं. निजी क्षेत्र में तो दोबारा टेस्ट, एक्स-रे आदि के लिए आदेश हो जाता है. हमारे देश में कई अच्छे डॉक्टर रोगी से जिज्ञासा के लिए भी सवाल पूछने पर नाराज हो जाते हैं. उनके लिखे पर्चे को दूसरे डॉक्टर या केमिस्ट मुश्किल से पढ़ पाते हैं. अमीर हो या गरीब, गंभीर स्वास्थ्य समस्या के दौरान थैले में पिछले आधे-गले-फटे रिकॉर्ड लिये दौड़ते रहते हैं.उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की हालत पर लगभग पांच वर्ष पहले सीएजी की एक रिपोर्ट में इस बात पर ध्यान दिलाया गया था कि उन अस्पतालों में रोगियों की चिकित्सा तक का समुचित रिकॉर्ड नहीं मिलना अनुचित है. इसके बाद केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 10.75 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करने के लिए डिजिटल व्यवस्था की. इसके अलावा 2022 तक डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने का कार्यक्रम बना है. वहीं टेलीमेडिसिन के प्रावधान और डॉयग्नोस्टिक लेबोरेटरी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा. कोरोना काल में ऐसी लेबोरेटरी बनने का काम युद्ध स्तर पर भी हुआ है. बड़े निजी अस्पतालों ने चिकित्सा के डिजिटल रिकॉर्ड बनाने का काम पहले शुरू किया हुआ है, लेकिन वे यह रिकॉर्ड अन्य अस्पतालों को नहीं देते हैं. मरीजों को उन पर ही निर्भर रहने को मजबूर होना पड़ता है. मोदी सरकार ने 2019 में नेशनल हेल्थ ब्लूप्रिंट बना कर सार्वजनिक किया, ताकि उस पर अधिकाधिक राय- सुझाव सामने आ सकें. इससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्यक्रम बनाने में सुविधा हो रही है. सरकार ने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षण के तौर पर स्वास्थ्य पहचान पत्र के लिए काम शुरू कर दिया है. नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम के अंतर्गत हेल्थ मास्टर डायरेक्टरी एंड रजिस्ट्री बनेगी. वेब हेल्थ पोर्टल, मोबाइल के लिए माइ हेल्थ एप, कॉल सेंटर, हेल्थ सूचना एक्सचेंज स्थापित होंगे. इस योजना को लेकर अभी से निजता के अधिकार और गोपनीयता के सवाल उठने लगे हैं. हालांकि आधार कार्ड की अनिवार्यता ही नहीं, जनगणना को लेकर भी ऐसी आपत्तियां उठायी जा रही हैं. निश्चय ही निजता के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार और भारत के विशेषज्ञ स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे. केवल भ्रम फैलाने और ऐसी क्रांतिकारी योजना को कानूनी दांव-पेंच में फंसाने से करोड़ों भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है. आजादी के 73 वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं मिलने से शिक्षा और चिकित्सा के सरकारी केंद्र दयनीय स्थिति में रहे हैं. नयी योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकारों को अधिकाधिक बजट का प्रावधान करना होगा. राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहचान पत्र होने पर आप सोचिए, नागरिक को कितनी सुविधा हो जायेगी. उसके स्वास्थ्य का रिकॉर्ड उस कार्ड के एक नंबर से देश के किसी भी हिस्से में देखा जा सकेगा. आप गांव में जन्मे हों या महानगर में अथवा नौकरी, काम-धंधे से किसी उम्र में कहीं भी हों, कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या होने पर उस कार्ड के साथ जिस डॉक्टर के पास या अस्पताल पहुंचेंगे, उसे यह जानकारी मिल सकेगी कि कभी आपको मलेरिया, बुखार, पेट, सांस, दिल की कोई परेशानी हुई या नहीं. हुई है, तो किन दवाइयों से उपचार हुआ है. दुर्घटना की स्थिति में तो और भी आसानी होगी, क्योंकि आप बोलने की हालत में भी नहीं होते. इससे तत्काल चिकित्सा के सभी उपाय किये जा सकेंगे. याद करें, जन-धन योजना में खाता खोलने और आधार कार्ड से जोड़ने पर एक वर्ग ने आपत्ति की थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान 20 करोड़ परिवारों के खातों में तत्काल छोटी ही सही, आवश्यक धनराशि मिल सकी.आयुष्मान भारत के तहत लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है. यदि आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, तो करोड़ों लोगों के साथ आपकी सेहत का विवरण भी दर्ज हो जायेगा, तो क्या कोई नुकसान हो जायेगा? जो अति ज्ञानी लोग गरीब लोगों की निजता की बात करते हैं, वे अमेरिका, चीन, रूस, यूरोप या दुबई की यात्रा के वीजा के लिए पूरे खानदान का ब्योरा देने, हेल्थ चेक अप के सारे रिकॉर्ड पेश करने में शान समझते हैं. अब भारत के गांव से शहर तक के गरीब, कम शिक्षित लोग अपना तथा देश का भला और बुरा समझने लगे हैं. शिक्षा और स्वास्थ्य की नयी क्रांति से देश का भविष्य अधिक सुरक्षित और खुशहाल हो सकेगा.

स्वराज नहीं है, अंग्रेजी राज की समाप्ति

जब औपनिवेशिक मनुष्य ने सोचना छोड़ दिया था और उसका समर्थ होने का अहसास लुप्त हो चुका था, गांधी ने उसे सोचना सिखाया और उसके सामर्थ्य के अहसास को पुनरुजीवित किया। नेल्सन मंडेला द्वारा किया गया महात्मा गांधी का यह सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन औद्योगिक-युग के मनुष्य के सम्मुख आज भी रोशनी के एक स्तंभ की तरह खड़ा नजर आता है। महात्मा गांधी के चिंतन के केन्द्र में सदैव मनुष्य रहा है, क्योंकि गांधी देख पा रहे थे कि औद्योगिक-युग ने चिन्तन के केन्द्र में वस्तुओं को लाकर खड़ा कर दिया है। गांधी के चिन्तन को आगे बढ़ाने वाले लेखक ईएफ शुमाकर ने अपनी विश्व-प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी के विचार को आगे बढ़ाते हुए लिखा है -श्श्जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? वस्तुओं का विकास अथवा मनुष्यों का? और अगर हम मनुष्यों के विकास की बात करते हैं तो कौन से मनुष्य? वे कहां हैं? मनुष्य में दिलचस्पी लेने से ऐसे असंख्य सवाल उठेंगे। यूरोप में हुई औद्योगिक-क्रान्ति (1750-1850) के बाद बड़े पैमाने पर वस्तु-उत्पादन ने दुनिया को पहले बाजार की तलाश में उपनिवेशवाद और बाद में शक्ति-प्रदर्शन के लिए दो विश्वयुद्धों की ओर धकेल दिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उपनिवेशवाद से आजाद हुए देशों के सम्मुख विकास के सबसे ताकतवर दो मॉडल थे। पहला पूंजीवादी अमेरिका का मॉडल और दूसरा साम्यवादी सोवियत संघ का मॉडल। आजाद भारत ने इन दोनों विश्व-शक्तियों को मिलाकर मिश्रित-अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में आई आधुनिकता की लहर 1980 के दशक में उत्तर-आधुनिकता में बदल गई। वैश्विक विचारधारा और अर्थव्यवस्था के स्तर पर यह माना जाने लगा कि पूंजीवाद और समाजवाद की पद्धतियां बहुत अलग नहीं हैं, दोनों उद्योगवाद के ही दो पहलू हैं। इनके मूल आधार वही हैं, उनमें सिर्फ मालिकाना रिश्तों को कुछ बदलने की चेष्टा भर की गई है। इससे नया शक्तिशाली वर्ग पैदा हो रहा है, वह भी कुछ पहले जैसा ही है। (गिरधर राठी श्सोच-विचारश् उत्तर-आधुनिकता के दायरे) भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का तराजू 1980 के दशक से निजी-क्षेत्र के पक्ष में झुकता हुआ आखिरकार 1991 में वैश्वीकरण के हाथों में चला गया। उस समय एबीबी (स्विस-स्वीडिश व्यावसायिक समूह) ग्रुप के अध्यक्ष पर्सी बार्नविक की वैश्वीकरण की अवधारणा आज हमारे देश में साकार रूप ले रही है।

पर्सी बार्नविक के अनुसार-मेरे हिसाब से वैश्वीकरण का मतलब है कि मेरी कम्पनी को जहां चाहे वहां, जब तक चाहे तब तक, जो चाहे वो पैदा करने, जहां से चाहे कच्चा माल मंगाने और जहां चाहे तैयार माल बेचने की पूरी आजादी मिले और श्रम कानूनों व सामूहिक समझौतों के नाम पर उसके सामने रुकावटें न हों। वैश्वीकरण का एक ही मूल सिद्धांत है -बिग इज पावरफुल। यह विशाल पूंजीनिवेश, उत्पादन, वितरण और लाभ के पैरों पर चलता हुआ स्माल इज ब्यूटीफुल के सिद्धांत को रौंद कर आगे बढ़ता जा रहा है। सीटी कुरियन के शब्दों में विकास एक ऐसी सामाजिक-प्रक्रिया है जो एक समय पर कुछ लोगों के लिए दौलत और अन्य लोगों के लिए गरीबी पैदा करती है।श्श हमारा देश अत्यंत कम आमदनी वाले लोगों का एक ऐसा सागर बन गया है जिसके बीच समृद्धि के कुछ टापू उभर आए हैं। वैश्वीकरण और स्वतंत्र व्यापार की नीति के फलस्वरूप आज हमारी शहरी और ग्रामीण दोनों आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थाएं प्रश्नों के घेरे में खड़ी हो गई हैं। युद्धों में देशों की इमारतें धराशायी होती हैं, आज के इस कोरोना-संकट में श्मनुष्यश् धराशायी हो रहा है। इस प्राकृतिक और आर्थिक-सामाजिक संकट में मनुष्य की मृत्यु और उसके अंतिम संस्कार के दृश्य युद्धों की विभीषिका के दृश्यों से अधिक भयावह और अमानवीय हैं।

भारत ही नहीं यूरोप और अमेरिका के अनेक महानगरों में आधुनिक सभ्यता की प्रतीक मानी जाने वाली कार का आवागमन नगरीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित हो रहा है। यह अपने आप में औद्योगिक-सभ्यता पर एक कठोर टिप्पणी है। महानगरों की बहुमंजिला इमारतें, जो आधुनिक सभ्यता की प्रतीक हैं, भय के संदेश दे रही हैं। इन इमारतों को किसी ने ठीक ही वर्टिकल-झुग्गी-झोपड़ी कहा है। फ्रांस के बौद्धिक जागरण से विश्व को लोकतांत्रिक-सभ्यता का संदेश मिला है। आज फ्रांस में अपने महानगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित रूप देने की योजनाओं पर चिन्तन हो रहा है। ऐसे में कोरोना-संकट जैसे अनेक संकट भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। इस विश्वव्यापी संकट में पुनः एक बार गांधी के चिन्तन को नये परिवेश में समझना जरूरी है। गांधी की अनेक उक्तियां हमारे ऊपर मंडरा रही हैं। उनकी बातें विश्व को उसके नये संदर्भ में देखने की ताकत देती हैं। कभी दिवास्वप्न सी लगने वाली उनकी सलाहें धरती पर डोल रही हैं। उन्होंने कहा था -शताब्दी-दो शताब्दी बाद आज की ये विशाल नगरीय व्यवस्थाएं ऊर्जा, पर्यावरण और विशाल आवासीय संकट से ध्वस्त और मृत हो जाएंगी। ये चीन की दीवार और मिस्र के पिरामिड की तरह खंडहर बनकर नुमाइश की चीजों में तब्दील हो जाएंगी। सन् 1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद, गांधी देख पा रहे थे कि कुछ समय बाद भारत में अंग्रेजी शासन भी खत्म हो जायेगा। उनके अनुसार अंग्रेजी शासन का अन्त ही भारत का स्वराज नहीं था।श् गांधी समय-समय पर भारत के विकास की अवधारणा सामने रखते थे। उन्होंने सन् 1936 में अपने अखबार हरिजन में लिखा था- मेरा विश्वास है और मैंने इस बात को असंख्य बार दोहराया है कि भारत अपने चंद शहरों में नहीं, बल्कि सात लाख गांवों में बसा हुआ है, लेकिन हम शहरवासियों का खयाल है कि भारत शहरों में ही है और गांव का निर्माण शहरों की जरूरतें पूरी करने के लिए ही हुआ है। गांधी के चिन्तन के केन्द्र में मनुष्य है। वे मानते हैं कि मनुष्य का अपना नितान्त निजी जीवन भी है जो परिवार, ग्राम और राष्ट्र के सदस्य के रूप में प्रजातंत्र का सबसे सजीव अंग बनाता है। मनुष्य की ताकत से प्रजातंत्र ताकतवर बनता है और मनुष्य की कमजोरी से प्रजातंत्र और देश भी कमजोर होता है। हम कोरोना के इस संकट-काल में दुनिया के कई देशों को कमजोर होता देख रहे हैं। गिरधर राठी अपनी पुस्तक कल आज और कल में कहते हैं -गांधी और मार्क्स में जो भी फर्क हो, एक फर्क इनमें सबसे बड़ा है- मार्क्स को व्यवहार में उतारने की पुरजोर विश्वव्यापी कोशिशें पचासों बार हो चुकी हैं। गांधी को अमली जामा पहनाने की कोशिश किसी गली-मोहल्ले तक में नहीं हुई है, जबकि मार्क्सवाद की तरह गांधीवाद भी आचरण का दर्शन ही है।

आइसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग ए स्थगित

दुबई, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने कोविड-19 महामारी की वजह से आइसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग ए के रूप में अपने दूसरे आयोजन को स्थगित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की राह तैयार करने वाला तीन चैलेंज लीग ए आयोजन में से दूसरा आयोजन पहले मार्च में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे कोविड-19 महामारी की वजह से तब स्थगित करके 30 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान मलेशिया में आयोजित करने का फैसला लिया गया था। आयोजन को स्थगित करने का निर्णय सदस्यों और संबंधित सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद लिया गया। चैलेंज लीग ए तालिका में अंक और स्थान हासिल करने के लिए इसमें कनाडा, डेनमार्क, मलेशिया, कतर, सिंगापुर, वानुअतु को 15 लिस्ट-ए मैच खेलने थे। आइसीसी के आयोजन प्रमुख क्रिस टेटली ने कहा, हमने आइसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग ए की दूसरी सीरीज को स्थगित करने का फैसला किया है, जो अगले महीने मलेशिया में होने वाली थी। आइसीसी की प्राथमिकता खिलाड़ियों, कोचों, अधिकारियों, प्रशंसकों और खिलाड़ियों की भलाई और पूरे क्रिकेट समुदाय की रक्षा करना है। आपको बता दें कि आइसीसी ने इससे पहले कोविड 19 महामारी की वजह से इस साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाने वाली टी20 वर्ल्ड कप को भी स्थगित कर दिया था। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर नवंबर में खेला जाना था। हालांकि सीए ने भी इसे आयोजित करने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अब इसका आयोजन साल 2022 में किया जाएगा। इससे पहले अगले साल भारत में नवंबर में भी टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यही नहीं आइसीसी ने कोविड 19 महामारी की वजह से खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई नए नियम भी बनाए जिससे की खिलाड़ियों का एक-दूसरे से संपर्क नहीं हो पाए। इसमें विकेट के बाद खिलाड़ी हाथ नहीं मिला सकते या फिर गेंद पर लार के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया।

इंग्लैंड ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया, तीसरा टेस्ट ड्रॉ रहा

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला साउथैंप्टन में खेला गया। बारिश से बाधित तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और इसके साथ ही इंग्लैंड ने इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत दर्ज की। तीसरे टेस्ट के लिए जैक क्रॉले को %प्लेयर ऑफ द मैच% चुना गया जबकि मोहम्मद रिजवान व जोस बटलर को %प्लेयर ऑफ द सीरीज% का खिताब मिला। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मैच की पहली पारी में इंग्लैंड ने जोस बटलर के शतक व जैक क्रॉले के दोहरे शतक के दम पर 8 विकेट पर 583 रन बनाए और पारी की घोषणा कर दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम ने अपने कप्तान अजहर अली के शतक के दम पर पहली पारी में 273 रन बनाए। पहली पारी में इंग्लैंड को 310 रन की बड़ी बढ़त हासिल हुई थी। इसके बाद मेजबान टीम ने पाकिस्तान को फॉलो-ऑन दे दिया और दूसरी पारी में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट पर 187 रन बनाए। दूसरी पारी में पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज शान मसूद व आबिद अली के बीच 49 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इससे पहले कि ये जोड़ी और बड़ी साझेदारी कर पाते ब्रॉड ने शान मसूद को 18 रन पर LBW आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया। इसके बाद आबिद अली भी 42 रन बनाकर जेम्स एंडरसन की गेंद पर LBW आउट हो गए। कप्तान अजहर अली 31 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर जो रूट के हाथों कैच आउट हो गए। असद शफीक 21 रन बनाकर जो रूट का शिकार बने जबकि बाबर आजम 63 रन पर नाबाद रहे। दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से एंडरसन ने दो जबकि ब्रॉड व रूट ने एक-एक विकेट लिए। एंडरसन के लिए ये मैच एतिहासिक रहा और वो तेज गेंदबाज के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।

इसके अलावा वो टेस्ट में 600 विकेट का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के चौथे गेंदबाज बने। इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले भी वो पहले गेंदबाज बने। एंडरसन ने अपना 600वां शिकार अजहर अली को बनाया। पाकिस्तान को पहली पारी में अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई और ओपनर बल्लेबाज शान मसूद ने सिर्फ 4 रन पर अपना विकेट गंवा दिया। उन्हें जेम्स एंडरसन ने LBW आउट कर दिया। टीम के दूसरे ओपनर आबिद अली भी सिर्फ एक रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। एंडरसन की गेंद पर वो अपना कैच सिब्ले को थमा बैठे। बाबर आजम को भी एंडरसन ने ही आउट किया और वो 11 रन बनाकर LBW आउट हो गए। असद शफीक को 5 रन पर एंडरसन ने जो रूट को हाथों कैच आउट करवा दिया। फवाद आलम ने पाकिस्तान को निराश किया और अपना विकेट 21 रन पर गंवा बैठे। उन्हें डोम बेस ने जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। मो. रिजवान ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 53 रन बनाए और क्रिस वोक्स की गेंद पर जोस बटलर के हाथों कैच आउट हुए। याशिर साह 20 रन बनाकर ब्रॉड की गेंद पर कैच आउट हुए। शाहीन अफरीदी 3 रन जबकि मो. अब्बास एक रन बनाकर आउट हुए। टीम के कप्तान अजहर अली ने अपने टेस्ट करियर का 17वां शतक लगाया जबकि इंग्लैंड के खिलाफ ये उनका तीसरा शतक था। वो 141 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड को पहली पारी में पहला झटका पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने दिया। उन्होंने ओपनर बल्लेबाज रोरी बर्न्स को 6 रन पर कैच आउट करवा दिया। रोरी का कैच शान मसूद ने लपका। टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज सिब्ले को याशिर शाह ने अपना शिकार बनाया। शाह की गेंद पर वो 22 रन पर एलबीडब्यू आउट हुए। कप्तान जो रूट को नसीम शाह ने 29 रन पर आउट किया और उनका कैच मो. रिजवान ने पकड़ा। वहीं ओली पोप 4 रन बनाकर याशिर शाह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। जैक क्रॉले ने अपनी टीम के लिए गजब की पारी खेलते हुए 267 रन बनाए। वो शफीक की गेंद पर मो. रिजवान के हाथों स्टंप आउट हुए। उन्होंने 393 गेंदों का सामना किया। जोस बटलर ने भी टीम के लिए शतकीय पारी खेली और 152 रन बनाकर फवाद आलम की गेंद पर उन्हें के हाथों लपके गए। वहीं क्रिस वोक्स भी 40 रन बनाकर फवाद आलम का शिकार बने और याशिर शाह ने उनका कैच लपका। स्टुअर्ट ब्रॉड को 15 रन पर शाहीन अफरीदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। डोमिनिक बेस 27 रन पर नाबाद रहे। पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में शाहीन अफरीदी, याशिर शाह व फवाद आलम ने दो-दो जबकि नसीम शाह व असद शफीक को एक-एक सफलता मिली। इंग्लैंड ÷ रोरी बर्न्स, डोम सिब्ले, जैक क्रॉले, जो रूट (कप्तान), ओली पोप, जोस बटलर, क्रिस वोक्स, डोमिनिक बेस, जोफ्रा आर्चर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन। शान मसूद, आबिद अली, अजहर अली (कप्तान), बाबर आजम, अशद शफीक, फवाद आलम, मो. रिजवान, याशिर शाह, मो. अब्बास, शाहीन अफीदी, नसीम शाह।

धोनी अपना फेयरवेल मैच कहां खेलेंगे

वीवीएस लक्ष्मण ने बताया जगह का नाम

नई दिल्ली, एजेंसी। धोनी ने 15 अगस्त 2020 के दिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और इसके बाद ये बातें भी उठने लगी कि धौनी जैसे महान खिलाड़ी ने फेयरवेल मैच भी नहीं खेला। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इच्छा व्यक्त की थी कि रांची में एम एस धौनी का के विदाई मैच का आयोजन हो। अब दूसरी तरफ पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण को विश्वास है कि धौनी का फेयरवेल मैच चेपक में आयोजित किया जाएगा। एम एस धौनी का जन्म रांची में हुआ, लेकिन पिछले कई साल से चेन्नई उनका घेरलू मैदान जैसा है। वो आइपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2008 से लीड कर रहे हैं और तीन खिताब भी दिला चुके हैं। धौनी का चेन्नई में ऐसा प्रभाव है कि वहां के क्रिकेट फैंस उन्हें थाला या थलाइवा कहते हैं।

लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स के शो क्रिकेट कनेक्टेड में कहा कि हम सबको ये पता है कि माही सीएसके को लेकर काफी भावुक हैं। ये टीम सबसे सफल फ्रेंचाईजी माही की लीडरशिप में ही बनी है। वो इस टीम को खिताब दिलाने से लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि जब तक वो क्रिकेट खेलेंगे वो सीएसके की कप्तानी करते रहेंगे। मुझे लगता है कि धौनी के हर एक मूवमेंट को काफी बारीकी से देखा जाएगा। धौनी जितना वक्त मैदान पर बिताएंगे उस हर पल का फैंस आनंद लेंगे। उन्होंने कहा कि अब ये तय है कि धौनी भारतीय जर्सी में नहीं दिखेंगे ऐसे में उन्हें विश्वास है कि ये महान विकेटकीपर-बल्लेबाज अपना आखिरी मैच सीएसके के लिए आइपीएल में खेलेगा जिसका आयोजन चेपक में किया जाएगा। यानी वो आइपीएल में ही अब अपना फेयरवेल मैच खेलेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि मुझे लगता है कि एम एस धौनी जब सीएसके के लिए आखिरी मैच खेलेंगे वही उनका विदाई यानी फेयरवेल मैच होगा। मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का फेयरवेल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था मुझे लगता है कि धौनी का विदाई मैच चेपक में आयोजित किया जाएगा। यही नहीं सभी क्रिकेट फैंस ना सिर्फ भारत के बल्कि दुनियाभार के धौनी के आखिरी मैच को देख रहे होंगे। धौनी के आइपीएल भविष्य को लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। धौनी इस साल इस टीम की अगुआई कर रहे हैं, लेकिन वो आइपीएल 2021 में खेलेंगे या नहीं इसका पता फ्रेंचाइजी के अधिकारियों को भी नहीं है।

पाकिस्तानी कप्तान का बयान- धोनी की विरासत को हमेशा याद रखेगी क्रिकेट की दुनिया

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान टीम के सीमित ओवरों के कप्तान बाबर आजम ने मंगलवार को कहा है कि भारतीय टीम के महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी ने जो विरासत छोड़ी है, उसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। बाबर आजम का ये बयान उस समय आया है जब एमएस धौनी ने अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर को 15 अगस्त को अलविदा कहा है। धौनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए संन्यास की घोषणा की थी। बाबर आजम ने एमएस धौनी को लेकर ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ÷उल्लेखनीय करियर के लिए एमएस धौनी आपको बधाई क्रिकेट जगत में आपके नेतृत्व, लड़ाई की भावना और विरासत को हमेशा याद किया जाएगा। मैं आपके जीवन के हर पहलू में पर्याप्त प्रकाश और चमक की कामना करता हूं।÷ धौनी ने इंस्टाग्राम पर संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा था कि भरपूर प्रेम और समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे 7 बजकर 29 मिनट के बाद रिटायर समझा जाए। साल 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले महेंद्र सिंह धौनी ने अपना आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 के दौरान खेला था। ये मुकाबला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, जिसमें भारत को करीबी हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में धौनी 50 रन बनाकर आउट हो गए थे और टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। धौनी इसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर नहीं आए और फिर एकाएक वनडे और टी20 क्रिकेट से भी दूरी बनाने का फैसला कर लिया। एमएस धौनी ने जैसे ही संन्यास का ऐलान किया। कुछ ही मिनटों के बाद सुरेश रैना ने भी उनको ज्वाइन किया और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धौनी की महानता किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने देश को साल 2007 में टी20 विश्व कप, साल 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और साल 2013 में आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जिताया था। इस तरह धौनी दुनिया के एकमात्र कप्तान बने थे, जिन्होंने तीनों आइसीसी ट्रॉफियां देश को दिलाई थीं।

आईपीएल 2020 की मुख्य प्रायोजक का ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 2020 के सीजन के लिए मुख्य प्रायोजक का ऐलान हो गया है। ड्रीम इलेवन कंपनी ने आइपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। ये कंपनी चीनी मोबाइल कंपनी को 2020 के आइपीएल के बतौर मुख्य प्रायोजक रिप्लेस करेगी। आइपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए ड्रीम इलेवन ने वीवो की तरह मोटी बोली लगाई है। आइपीएल 2020 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाना है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआइ ने वीवो के साथ अपनी साझेदारी तोड़ ली थी, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसी विवाद के बाद भारत में चीनी सामानों के खिलाफ बहिष्कार शुरू हो गया था। ऐसे में बीसीसीआइ ने विवादों से बचने के लिए वीवो के साथ 2020 के लिए साझेदारी से समझौता कर लिया था। लीडिंग फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन में टाटा ग्रुप और अनअकेडमी जैसे आइपीएल के मुख्य प्रायोजक के दावेदारों को चित करते हुए बोली लगाई और जीती। इस बोली में दूसरे नंबर पर अनअकेडमी रही, जबकि तीसरे नंबर पर टाटा संस ने बोली लगाई। ड्रीम 11 ने 250 करोड़ रुपये की बोली के साथ आइपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर की डील में बाजी मारी है। हालांकि, वीवो जितना एक साल के आइपीएल के बीसीसीआइ को रकम(एक साल के लिए 440 करोड़) अदा करती थी, उससे कम रकम में बीसीसीआइ को नया स्पॉन्सर मिला है। इससे पहले कहा जा रहा था कि आइपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की रेस ड्रीम इलेवन के अलावा बायजू, अनअकेडमी, टाटा संस और पतंजलि के बीच होगी, लेकिन बायजू और पतंजलि रेस में काफी पीछे रह गईं, जबकि बाजी ड्रीम 11 ने मारी। हालांकि, बीसीसीआइ और ड्रीम 11 के बीच ये करार सिर्फ चार महीने का होगा। इस बात का ऐलान बीसीसीआइ ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि आगे फिर से बीसीसीआइ को वीवो के साथ हाथ मिलाना है।

रिटायरमेंट से बाद आईपीएल में कैसा है धोनी का भविष्य

नई दिल्ली, एजेंसी। अपने फैसलों की वजह से ही अपने क्रिकेट करियर में इतने सफल रहे। एम एस की ये खासियत रही कि वो कभी भी फैसला लेने में कोताही नहीं बरतते थे और सही वक्त पर सही फैसला ही उनकी सफलता का मूलमंत्र रहा। मैदान के अंदर की बात करें या फिर बाहर की उन्होंने अपने हर फैसले से हमेशा ही सबको चौंकाया। बात उनकी शादी की हो या फिर कप्तानी छोड़ने से लेकर रिटायरमेंट लेने तक की, माही ने सारे फैसले अचानक ही किए। 39 साल के सबसे सफल कप्तान ने 15 अगस्त 2020 के दिन अपने 16 साल पुराने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। माही अब ब्लू नहीं बल्कि पीली जर्सी में

आइपीएल में नजर आएंगे, लेकिन कब तक ये साफ नहीं है पर सीएसके फ्रेंचाइजी के सीईओ काशी विश्वनाथन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उनके आइपीएल भविष्य के बारे में बताया। उन्होंने धौनी के संन्यास के बाद उनसे आइपीएल भविष्य के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अभी सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वो सीएसके के लिए खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जब तक चाहें हमारे लिए खेल सकते हैं। सच तो ये है कि हम उन्हें साल 2021 आइपीएल के बाद भी एक खिलाड़ी के तौर पर रिटेन करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला धौनी का था और जब वो इस तरह से फैसले करते हैं तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि, हम निश्चित तौर से हम ये आशा करते हैं कि वो सीएसके को छोड़ने का फैसला इस तरह से नहीं करेंगे। विश्वनाथन ने आगे कहा कि धौनी का ये फैसला हमें चकित कर गया, लेकिन उन्होंने कोई भी भावना नहीं दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम और सीएसके को धौनी की कप्तानी में इतनी सफलता मिली क्योंकि उनके विचारों में स्पष्टता थी। शनिवार को भी धौनी के निर्णय में मैं वहीं स्पष्टता देख सकता था।

धोनी से ज्यादा टैलेंटेज हैं रिषभ पंत, उनसे बेहतर खिलाड़ी हो सकते हैं साबित

नई दिल्ली। 23 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए पहली बार साल 2004 में डेब्यू किया था और 39 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। धौनी के संन्यास लेने से पहले से ही रिषभ पंत को उनका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन लगातार मौके दिए जाने के बावजूद वो खुद को साबित नहीं कर पाए थे। अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का कहना है कि 22 साल की उम्र में रिषभ पंत के पास 23 साल की उम्र में टीम इंडिया में खेलने आए एम एस धौनी के मुकाबले ज्यादा नैचुरल टैलेंट है। वैसे पंत को अपने खराब शॉट्स की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। रिषभ पंत टीम इंडिया के वनडे और टी20 टीम का हिस्सा लगातार रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने अब उनकी जगह केएल राहुल को तवज्जो देना शुरू कर दिया है क्योंकि पंत की गैरमौजूदगी में उन्होंने टीम के लिए बखूबी विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका भी निभाई और सफल भी रहे। हालांकि केएल राहुल द्वारा इस भूमिका के निभाए जाने के बाद टीम के पास ज्यादा विकल्प हैं। वहीं दूसरी तरफ आशीष नेहरा का कहना है कि अगर रिषभ पंत अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर पाए तो वो भारत के लिए एम एस धौनी से भी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि आशीष नेहरा ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि इतना सबकुछ हासिल करने के लिए रिषभ पंत को उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी एम एस धौनी ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में की है। नेहरा ने आगे कहा कि रिषभ पंत सिर्फ 14 साल की उम्र से सोनट क्लब में थे। यकीन मानिए 22 साल की उम्र रिषभ पंत के पास जितना नैचुरल टैलेंट है।

ईशांत शर्मा सहित 29 खिलाड़ियों के नामों की अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और तीरंदाज अतनु दास सहित 29 खिलाड़ियों की खेल मंत्रालय की चयन समिति ने इस साल अर्जुन अवॉर्ड के लिए सिफारिश की है। मंत्रालय के ऑफिशियल अधिकारी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों में महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, क्रिकेटर दीपक हुड्डा और टेनिस खिलाड़ी दिविज शरण का नाम भी शामिल है। ईशांत शर्मा के करियर की बात करें तो इस तेज गेंदबाज ने 97 टेस्ट में 297 विकेट लिए हैं, जिसमें 11 बार 5 विकेट भी शामिल हैं। ईशांत पिछला मैच इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड में खेले थे। ईशांत के नाम 80 वनडे मैचों में 115 विकेट हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनके लिए कहा था कि इशांत टेस्ट टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और भारत को नंबर-1 टीम बनाने में उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। इसमें कहा गया कि अर्जुन अवॉर्ड की सिफारिश के लिए ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और पूर्व वर्ल्ड चैम्पियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू का भी नाम शामिल था लेकिन खेलमंत्री किरेन रीजिजू ने फाइनल निर्णय लेते हुए उनका नाम हटा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों महिलाएं पहले खेल रत्न अवॉर्ड पा चुकी हैं। साक्षी ने 2016 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की वजह से खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया था जबकि मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने की वजह से 2018 में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ यह अवॉर्ड जीता था।

कंगना रनौत ने बाय काट कंगना पर दिया मुंहतोड़ जवाब

खुद को सैनिटाइजर कहकर इन स्टार्स को बताया वायरस

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई हैं। वैसे सुशांत के आत्महत्या कर लेने के बाद से फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ सोशल मीडिया पर मूवी माफिया और नेपोटिज्म को लेकर आए दिन खूब बहस होती रहती है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने सुशांत की मौत के मामले में फिल्म जगत के कई लोगों का नाम लेकर नेपोटिज्म की बात बोली है। इन दिनों कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। ऐसे में ट्विटर पर कंगना को लेकर हैशटैग ट्रेंड करने लगा,जिसके बाद खुद सामने आई कंगना ने ट्रोलर्स कि बोलती बंद कर दी है। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने ट्विटर पर एंट्री मारी है।

इसके साथ ही वह सुशांत सिंह राजपूत केस पर भी खुलकर राय रख रही हैं। वैसे अभिनेत्री फिल्म जगत में कई मुद्दों को लेकर मुखर रही हैं और वह अपनी कोई भी बात कहने में भी नहीं हिचकती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कंगना के फैंस उन्हें बेबाकी के लिए काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इतना ही नहीं बॉलीवुड क्वीन ने अपने ट्विटर पर मीम को शेयर करते हुए लिखा,चूहों वापस बिल में चले जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। फिल्मी स्टाइल हूल देनी है तो ऐसे देते हैं, ट्रेंड से मुझे डर नहीं लगता जाओ कुछ और ट्राई करो। बता दें हालिया में कंगना को ट्विटर पर बाय काट के साथ जमकर ट्रोल किया गया है। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक मीम ट्वीट करते हुए ट्रोलर को करारा जवाब दे डाला है, उन्होंने एक मीम शेयर किया जिसमें उन्होंने खुद को सैनिटाइजर बताया है,लेकिन करण जौहर, वरुण धवन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को वायरस करार दिया। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर कंगना रनौत ने कई सारे बड़े खुलासे करते हुए इसे एक प्लान्ड मर्डर बताया है। वहीं सुशांत मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है।

अब भी कर रहा है सुशांत का पेट डॉग फज उनका इंतजार, ऐसे लगाता है बाइक के चक्कर

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आए दिन हैरान करने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। सुशांत को गए हुए दो महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। फ्लिहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। एक्टर के पुराने वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनके फैंस, दोस्त और परिवार द्वारा साझा किया जा रहा है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल सुशांत के डॉग फज का हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है सुशांत सिंह राजपूत का आज भी फज इंतजार करता है। फज के इस वायरल वीडियो को लेकर अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि का का है। हालांकि जिसने भी यह वीडियो देखा है वह फज के लिए उदास हो गया है। वीडियो में देख सकते हैं कि सुशांत की बाइक के चक्कर उनका पालतू कुत्ता फज लगाता नजर आ रहा है। दरअसल बच्चों की तरह अपने पेट डॉग फज को सुशांत सिंह प्यार करते थे। जब सुशांत के निधन की खबरें आई थी उसके बाद ही सोशल मीडिया पर कई वीडियोज उनके डॉगी के वायरल होने लग गए थे। वैसे तो फज का वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुशांत की भांजी मल्लिका सिंह ने शेयर किया था। मल्लिका ने वीडियो के साथ लिखा था कि, फज अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से दरवाजे की ओर देखता रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार के पटना स्थित घर पर सुशांत का परिवार फज को सुशांत के निधन के बाद अपने साथ ले गए हैं।

हालांकि फज के साथ सुशांत के पिता केके सिंह की एक तस्वीर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर साझा की थी जिसमें दोनों एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर को खूब पसंद फैंस ने किया था। अब सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्य इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के अलावा सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी के खिलाफ जांच एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। केस के हर पहलू, हर गवाह और हर शक पर लगातार ब्ठप् की टीमें काम कर रही हैं।

संजय दत्त को मिला यूएस के लिए 5 साल का वीजा

कैंसर के इलाज के लिए जल्द जाएंगे न्यूयॉर्क

संजय दत्त को बीते दिनों कैंसर का पता चला है। वह अपना शुरुआती इलाज मुंबई में ही करवा रहे थे। अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, वह इलाज के लिए यूएस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजय दत्त को लंग कैंसर है। एक न्यूज पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, संजय को कैंसर का पता चलते ही उन्होंने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था। हालांकि शुरुआत में उन्हें क्लीयरेंस मिलने में मुश्किल आ रही थी क्योंकि वह 1993 ब्लास्ट के दोषियों में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके एक करीबी दोस्त ने उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर 5 साल का वीजा दिलवा दिया है। अब उम्मीद है कि वह अपनी पत्नी मान्यता और बहन प्रिया के साथ न्यूयॉर्क जाकर कैंसर का इलाज करवाएंगे। संजय दत्त की मां नरगिस को भी 1980 और 1981 में कैंसर हुआ था। रिपोर्ट्स हैं कि उनको भी इसी हॉस्पिटल में ऐडमिट करवाया गया था। सिर्फ वह ही नहीं ऋषि कपूर, मनीषा कोइराला और सोनाली बेंद्रे ने भी इसी अस्पताल में इलाज करवाया है। खबर यह भी है कि यूएस जाने का प्लान नहीं कामयाब हो पाया तो संजय दत्त सिंगापुर जाएंगे।

सुधार के लिए करना होगा इंतजार

मुंबई, एजेंसी। देश में लॉकडाउन में ढील के साथ आर्थिक गतिविधियों ने कुछ जोर पकड़ा है मगर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को लगता है कि गतिविधियां कुछ और समय तक मंद ही रह सकती हैं क्योंकि कुछ रायों ने सख्ती के साथ दोबारा लॉकडाउन लागू कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी सालाना रिपोर्ट में यह भी कहा कि कोविड-19 का टीका मिलने के बाद प्रोत्साहन के उपाय वापस लेना जरूरी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक गतिविधियों में अभूतपूर्व कमी आई है। लॉकडाउन में ढील के बाद मई और जून में गतिविधियां तेज हुई थीं मगर कई रायों में दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाए जाने से जुलाई और अगस्त में सारी तेजी गायब हो गई। इससे लगता है कि दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों में कमी आएगी। केंद्रीय बैंक ने कहा कि खपत को तगड़ा झटका लगा है और हालात सुधरने तथा महामारी से पहले जैसी खपत होने में कुछ समय लग जाएगा। महामारी से लडने के लिए सरकारी खर्च बहुत बढ़ाया जा चुका है, इसलिए मांग पर आधारित गतिविधियों में काफी कमी आएगी। रिपोर्ट में कहा गया, सरकारी वित्त का इतना इस्तेमाल कर लिया गया है कि वृद्धि के लिए पूंजीगत खर्च में कमी लाजिमी लग रही है।

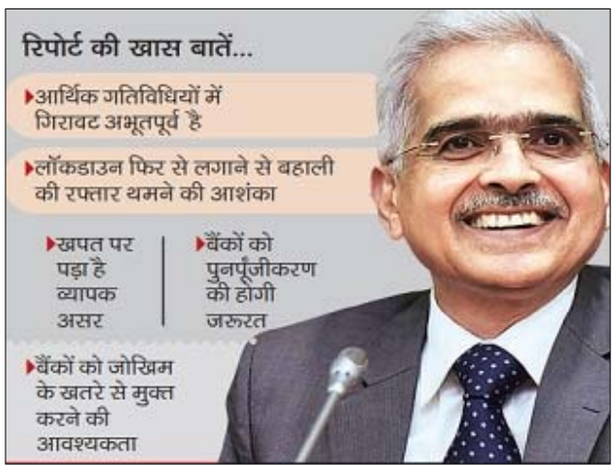

महामारी के दौरान रुके कर्ज और दूसरी देनदारी की वजह से भविष्य में वित्तीय नीति काफी बदली होगी। रिपोर्ट कहती है, खजाना मजबूत करने की भरोसेमंद योजना ही अब कारगर होगी, जिसमें कर्ज तथा राजकोषीय घाटा कम करने के सटीक उपाय बताए जाएं। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि सरकार को कर भुगतान में डिफॉल्ट करने वालों का पता लगाने और कर आधार बढ़ाने के लिए बिग डेटा तथा तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नियम उपयुक्त और सरल बनाने चाहिए। रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए और श्रम का यादा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राय और केंद्र सरकार को स्टील, कोयला, बिजली, जमीन तथा रेलवे की संपत्तियों से कमाई की संभावना तलाशनी चाहिए और प्रमुख बंदरगाहों के निजीकरण पर विचार करना चाहिए। आरबीआई के अनुसार बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अब कंपनी जगत के लिए रकम के प्राथमिक स्रोत का अपना दर्जा खो रही हैं क्योंकि अब कंपनियां पूंजी और बॉन्ड बाजार पर यादा ध्याना दे रही हैं। फिर भी वित्तीय कंपनियों को जोखिम से बचने की अपनी आदत छोडनी होगी क्योंकि उसके कारण अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को कर्ज मिलने में अड़चन आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है, संकट अपने साथ अवसर भी लाया है और भविष्य ती तस्वीर इस बात से तय होगी कि उनका फायदा कैसे उठाया जाता है। वृहद आर्थिक मोर्चों पर नरमी से बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और लाभदेयता प्रभावित होगी। रिपोर्ट कहती है, महामारी के कारण कर्ज भुगतान में मॉरेटोरियम, ब्याज भुगतान को टालने और कर्ज पुनर्गठन जैसे नियामकीय उपाय जरूरी हो गए हैं मगर उन पर ठीक से नजर नहीं रखी गई और सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो बैंकों की माली हालत पर असर पड़ सकता है। नियामकीय रियायतों और उपायों ने महामारी के कारण बिगड़ी स्थिति पर पर्दा डाल दिया है मगर आगे जाकर हकीकत सामने आएगी। वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट के जून संस्करण में बताया गया था कि गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) मार्च 2020 के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ सकती हैं और स्थिति बहुत गंभीर हुई तो 1.7 गुना इजाफा भी हो सकता है। मार्च 2021 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2020 के मुकाबले 13.3 फीसदी ही रह जाएगा। इसलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने की जरूरत होगी। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों ने प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए महंगाई काबू करने के फेर में अपनी बैलेंस शीट पर दबाव बना लिया है। ब्याज दरें असामान्य तौर पर कम रखने का मतलब है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कर्ज बेलगाम तरीके से बढना क्योंकि कर्ज चुकाने का दबाव ही नहीं है। 30 जून को आरबीआई की बैलेंस शीट 30.02 फीसदी बढ़ी है। केंद्रीय बैंक ने अपनी आपात निधि में 73,615 करोड़ रुपये डाले हैं। सरकार को कुल 57,128 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित किया गया जबकि पिछले साल 1.76 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। केंद्रीय बैंक के पास घरेलू बॉन्ड में 11.7 लाख करोड़ रुपये के घरेलू बॉन्ड और 10.2 लाख करोड़ रुपये के विदेशी बॉन्ड हैं। एक साल पहले इसी समय उसके 9.9 लाख करोड़ रुपये के घरेलू और 7 लाख करोड़ रुपये के विदेशी बॉन्ड थे।सालाना रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2019-20 में बैंक धोखाधड़ी के मामले 159 फीसदी बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये हो गए। जाली (नकली) नोटों की संख्या भी 144.6 फीसदी बढ़ी है। इनमें 10, 50, 200 और 500 रुपये के नोट शामिल हैं। हालांकि 20, 100 और 2,000 रुपये के पकड़े गए नकली नोटों की संख्या में कमी आई है।

ब्रांडों का नया दांव डिजिटल फिल्म रिलीज पर

कोरोनावायरस महामारी के बीच डिजिटल माध्यम पर फिल्में रिलीज कराने का रुझान बढ़ रहा है ऐसे में ब्रांडों ने भी लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मंचों के साथ साझेदारी करना शुरू कर दिया है। ब्रांडों का कहना है कि डिजिटल माध्यम के जरिये फिलहाल फिल्में, शो, वेब सीरीज देखने के रुझान में नाटकीय रूप से तेजी आई है। लोग आम तौर पर नई और अछी सामग्री देखना चाहते हैं जबकि यादातर टेलीविजन चैनल नई सामग्री दर्शकों के लिए पेश नहीं कर पा रहे हैं। फिल्में रिलीज होना लगभग बंद हो गया है और निर्माता फिल्मों को ओटीटी मंचों पर रिलीज कराने का विकल्प चुन रहे हैं जिसकी वजह से ब्रांडों को गठजोड़ करना पड़ रहा है। टाटा टी गोल्ड और पारले-जी ने मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन अभिनीत फिल्म शकुंतला देवी के लिए एमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ करार किया है। टाटा कंयूमर प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष (मार्केटिंग, बेवरिज इंडिया) पुनीत दास का कहना है कि हाल के दिनों में इस तरह का गठजोड़ इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि हाल के वक्त में इस तरह के मंचों की प्रासंगिकता बढ़ी है। ओटीटी/ऑनलाइन स्ट्रीमिंग खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी वजह से यह साझेदारी वास्तव में इस मायने में अनूठा है कि इससे प्राइम वीडियो मूवी साझेदारी के जरिये ब्रांड के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी और एमेजॉन डॉट इन के साथ गठजोड़ से टाटा टी गोल्ड का ग्राहकों तक पहुंचने का सफर पूरा होगा। दास कहते हैं, इससे हमें ब्रांड की मूल बात को मजबूत बनाने में मदद मिलती है और साथ ही एमेजॉन डॉट इन के साथ गठजोड़ से खरीदारी के लिए उपभोक्ता का रास्ता और सरल हो जाएगा। लॉकडाउन लगाए जाने और सिनेमा हॉल को अभी कुछ और दिन तक बंद रखने की योजना के साथ ही ओटीटी पर फिल्में रिलीज करना अब मनोरंजन की दुनिया के लिए सामान्य बात होने लगी है। ऐसे में इस तरह के गठजोड़ और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि हाल के वक्त में ओटीटी/ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर दर्शकों की तादाद काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे डिजिटल दौर ग्राहकों के नए अनुभवों को आकार दे रहा है और कैसे एक ब्रांड के रूप में टाटा टी गोल्ड इस बदलते समय में आगे रहने के लिए नए प्रयोग कर रहा है। भारत की प्रमुख बिस्कुट और कन्फेक्शनरी निर्माता कंपनी पारले प्रोडक्ट्स ने एमेजॉन प्राइम वीडियो पर एक नई साझेदारी वाले ब्रांड वीडियो लॉन्च कर फिल्म शंकुतला देवी के लिए भी साझेदारी की है जिसे ओटीटी और डिजिटल मंचों पर दिखाया जाएगा। पारले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह कहते हैं, आम तौर पर हम फिल्मों के साथ करार नहीं करते हैं क्योंकि यादातर वक्त में यह जबरदस्ती का गठजोड़ लगता है लेकिन इस बार हमने इस फिल्म के साथ एक स्वाभाविक मेल महसूस किया। यह फिल्म एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के बारे में हैं और हमारी ब्रांड पोजिशनिंग के लिहाज से यह फिल्म बिल्कुल मुफीद है। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में अगर आप डिजिटल सामग्री की खपत पर गौर करें तो आपको इसमें नाटकीय रूप से इजाफा दिखेगा। यादातर टीवी चैनल नई सामग्री नहीं पेश कर रहे हैं। फिल्में ओटीटी मंचों पर रिलीज हो रही हैं क्योंकि सिनेमाघर अब भी बंद हैं। फिल्म शकुंतला देवी लॉकडाउन के 3-4 महीने के अंतराल के बाद लॉन्च हो रही पहली कुछ फिल्मों में से एक है। इस वक्त रिलीज की जा रही फिल्मों के लिए लोगों में काफी दिलचस्पी है क्योंकि ये काफी लंबे अंतराल के बाद रिलीज की जा रही हैं।

इस बार त्योहार में कार पर नहीं होगी छूट की बौछार!

मुंबई, एजेंसी। अगर आप इस साल त्योहारों पर कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपको उम्मीद है कि कंपनियां अपनी गाडियों पर भारी छूट या तोहफे देंगी तो आपके हाथ मायूसी ही लग सकती है। कोविड-19 महामारी के हिचकोलों से बेजार कार कंपनियां इस बार बिक्री बढ़ाने वाली त्योहारी छूट और दूसरे तोहफों से तौबा कर सकती हैं। इस बार कंपनियों की योजना कुछ अलग है। वे ग्राहकों को लुभाने के लिए गाडियों पर कर्ज की आकर्षक योजनाएं और बेहतर डिजिटल सहूलियत लाने के बारे में सोच रही हैं। कार कंपनियां अमूमन गणेश चतुर्थी से दीवाली तक जमकर बिक्री करती हैं। उनकी साल भर की बिक्री में 17 से 19 फीसदी योगदान इसी दौरान हुई बिक्री का होता है। जाहिर है, इतने कम समय में इतनी अधिक बिक्री की वजह से ये त्योहार कंपनियों के लिए बेहद अहमियत रखते हैं। मगर इस बार माजरा अलग ही है। कार कंपनियों के अधिकारी और प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस साल काफी कठिन दौर चल रहा है। मारुति सुजूकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव कहते हैं, कार कंपनियों को इस बार त्योहारों पर बिक्री बढ़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

इस बार छूट या दूसरे ऑफरों की गुंजाइश नहीं के बराबर है, इसलिए कार कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए नए तरीके तलाशने और आजमाने पड़ेंगे।श्रीवास्तव यह भी कहते हैं कि त्योहार अछी तरह से गुजारने के लिए कंपनियों को

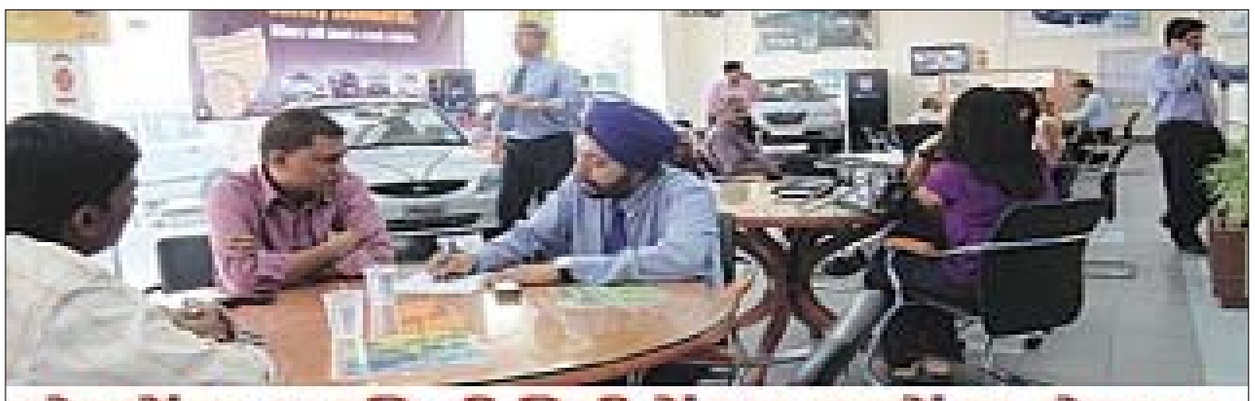

त्योहारों पर मारुति की बिक्री में कुछ राज्यों का योगदान

राज्य	त्योहार	खुदरा बिक्री में प्रतिशत हिस्सेदारी
केरल	ओणम	13-14
गुजरात	नवरात्र	13-14
पश्चिम बंगाल	दुर्गापूजा	8-9
देश में औसत	नवरात्र/दीवाली	16-17
उद्योग का औसत	नवरात्र/दीवाली	17-19

स्रोतः मारुति

सुनिश्चित करना होगा कि जून से बिक्री में आई रफ्तार को बकरार रखा जाए और पहले से यादा तेजी दी जाए। मगर दिक्कत यह है कि यह सारा काम उन्हें पिछले साल के मुकाबले बेहद कम बजट में करना पड़ेगा क्योंकि महामारी की चोट खाई कंपनियां यादा से यादा नकदी अपने पास रखना चाहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियों के सामने न केवल पहली तिमाही में हुए नुकसान की भरपाई करने की चुनौती है बल्कि पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी त्योहारों पर जमकर कारें बेचने का दबाव है। इस दौर में यह गंभीर चुनौती है क्योंकि ग्राहक भी आर्थिक अनिश्चितता के बीच सोच विचार कर खरीदारी कर रहे हैं। फिर भी कंपनियां अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति त्योहारों पर कोई नया मॉडल शायद ही उतारेगी मगर कंपनी कार के लिए कर्ज लेने की सुविध पूरी तरह डिजिटल करने की तैयारी में है। इससे ग्राहकों को कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। उसके बजाय घर बैठे ही सब कुछ हो जाएगा और ग्राहक को कर्ज मिल जाएगा यानी कर्ज की योजना चुनने से लेकर उसकी मंजूरी और रकम के आवंटन तक सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा। श्रीवास्तव कहते हैं, कार कंपनियां अभी तक कर्ज से जुड़े झंझटों और तामझाम से दूर रहती आई हैं। यही वजह थी कि ग्राहकों को पहले कर्ज मंजूर कराने के लिए बैंक तक जाना पड़ता था। मगर श्रीवास्तव ने बताया कि अब ई-फाइनैंस विकल्प के तहत घर बैठे ही कर्ज हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस नई योजना का परीक्षण भी शुरू हो गया है। परामर्श फर्म पीडब्ल्यूसी में पार्टनर एवं लीडर कवन मुख्त्यार का कहना है कि कार कंपनियों के सामने इस त्योहारी सत्र में कारों की बिक्री पटरी पर लाने की एक कठिन चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले कारों की बिक्री 20 फीसदी कम रहेगी, लेकिन त्योहारों पर कारोबार बढिया रहा तो कंपनियां कुछ हद तक भरपाई कर लेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि रुकी बिक्री फिर शुरू होने और महामारी के इस दौर में निजी वाहन की जरूरत बढने के कारण जून से वाहनों की बिक्री में थोड़ी तेजी दिखी है। विश्लेषकों और वाहन उद्योग के लोगों के अनुसार इस वजह से भी कार कंपनियां त्योहारों में बिक्री बढ़ाने के लिए यादा हाथ-पांव मारने की जरूरत नहीं है।महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के मुख्य कार्याधिकारी (वाहन खंड) विजय नाकरा कहते हैं, वाहनों की मांग में काफी हद तक तेजी दिखी है। इसलिए हमें अतिरिक्त छूट एवं प्रोत्साहन आदि देने की जरुरत महसूस नहीं हो रही है। हमें तो यह लग रहा है कि वाहन उद्योग में ग्राहकों के लिए ऑफर कमोबेश एक समान या पिछले वर्ष से कम ही रहेंगे। हुंडई मोटर इंडिया में निदेशक (बिक्री एवं विपणन) तरुण गर्ग कुछ अधिक उत्साहित हैं। वह कहते हैं, हमारे लिए इस वर्ष त्योहारी मौसम काफी पहले शुरू हो गया। दरअसल उनका इशारा कंपनी के क्रेटा, वेरना और ऑरा समेत नए मॉडलों को ग्राहकों की अछी प्रतिक्रिया मिलने की ओर था। गर्ग ने कहा कि अगस्त में हुंडई बिक्री के मामले में पिछले साल के औसत के बराबर पहुंच गई है और अब बिक्री खुद-ब-खुद हो रही है। इसलिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट जानें 17 जुलाई का ताजा भाव

नई दिल्ली, एजेंसी। कमजोर मांग और कोरोना वायरस का टीका जल्द बाजार में आने की उम्मीद के कारण शुक्रवार को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट आई है। शुक्रवार सुबह देशभर के सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 182 रुपये सस्ता होकर 49085 रुपये पर खुला। वहीं चांदी में आज 340 रुपये प्रति किलोग्राम की नरमी देखी जा रही है। अब चांदी का भाव 52000 रुपये के काफी नीचे आ गया है। पिछले एक साल में गोल्ड 40 फीसद रिटर्न दे चुका है। सोना अभी भी अपने सर्वोच्च कीमत के आसपास बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोना मुद्रास्फीति की मार को कम करेगा। आमतौर पर वैश्विक उथल-पुथल के समय में इक्विटी और डेब्ट की तुलना में सोना बेहतर प्रदर्शन करता है। आपके पोर्टफोलियो में सोने का होना आपके न केवल नुकसान की भरपाई कर सकता है बल्कि मुनाफा भी दे सकता है। एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (कमोडिटी एंड करंसी), अनुज गुप्ता के मुताबिक कोरोना संकट के बीच जिस तेजी से सोने की कीमत बढ़ी है उसके अनुपात में चांदी की नहीं बढ़ी है। वर्तमान में सोने और चांदी के बीच का अनुपात 92.90 है, हालांकि वर्ष 2020 की शुरुआत में यह 83.72 के आसपास था। ऐसे में चांदी की कीमत आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ने की पूरी संभावना है। इस महीने की बात करें तो बचे हुए दो हफ्तों में चांदी 1700 से 1800 रुपये महंगी हो सकती है। महीने के अंत तक चांदी 54,000 से 55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच सकती है।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
संपादक- कंचन सोलंकी
TITLE CODE- UPHIN48974
Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com
नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।